VAID'S ICS LUCKNOW
IAS/PCS/PCS-J

VAID ICS LUCKNOW

UPSE (CSE)- PRE 2026

TEST BOOKLET SERIES

TEST CODE 2025

SECTIONAL MOCK TEST-1
(INDIAN ECONOMY)
Dated: 15.11.2025

A

(ANSWERS WITH EXPLANATIONS)

1. Answer- (a)

Explanation- Statement 1 is correct. Gross National Product (GNP) measures the market value of all final goods and services produced by the residents or nationals of a country, both domestically and abroad, over a specific time period. It includes the income earned by citizens working abroad and excludes the income earned by foreigners working domestically. In contrast, **Gross Domestic Product (GDP)** measures the market value of all final goods and services produced within a country's geographical borders, irrespective of the nationality of the producer. Thus, GNP is based on nationality (residency) principle, and GDP is based on the territorial principle.

Statement 2 is incorrect. The Human Development Index (HDI) is a **geometric mean** (not a simple average) of normalized indices for the three key dimensions: **Health** (measured by Life Expectancy at Birth), **Education** (measured by Mean Years of Schooling for adults and Expected Years of Schooling for children), and **Standard of Living** (measured by Gross National Income (GNI) per capita in PPP terms, not just Per Capita Income). The use of the geometric mean ensures that poor performance in any one dimension is not fully compensated by high performance in another.

व्याख्या- कथन 1 सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) किसी विशिष्ट समयावधि में देश के निवासियों या नागरिकों द्वारा, घरेलू और विदेश दोनों में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को मापता है। इसमें विदेशों में काम करने वाले नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है और देश के भीतर काम करने वाले विदेशियों द्वारा अर्जित आय को बाहर रखा जाता है। इसके विपरीत, **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** उत्पादक की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को मापता है। इस प्रकार, GNP राष्ट्रीयता (निवासी) सिद्धांत पर आधारित है, और GDP क्षेत्रीय सिद्धांत पर आधारित है।

कथन 2 गलत है। मानव विकास सूचकांक (HDI) तीन प्रमुख आयामों: **स्वास्थ्य** (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है), **शिक्षा** (वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है), और **जीवन स्तर** (क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) से मापा जाता है, न कि केवल प्रति व्यक्ति आय से) के लिए सामान्यीकृत सूचकांकों का **ज्यामितीय माध्य** (साधारण औसत नहीं) है। ज्यामितीय माध्य का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक आयाम में खराब प्रदर्शन की भरपाई दूसरे आयाम में उच्च प्रदर्शन से पूरी तरह से न हो जाए।

2. Answer- (b)

Explanation- tatement (b) is **correct**. The **Wholesale Price Index (WPI)** in India measures inflation at the producer or wholesale level. The **current base year** for WPI is indeed **2011-12**, and the largest weight in the WPI basket is assigned to **Manufactured Products** (around 64.23%), followed by Primary Articles and Fuel & Power.

Statement (a) is incorrect. The WPI tracks prices at the wholesale level, not the retail level. The **Consumer Price Index (CPI)** captures the change in the average price level at the retail level.

Statement (c) is incorrect. The Reserve Bank of India (RBI) has adopted the combined **Consumer Price Index (CPI-C)** as the key measure for its primary monetary policy objective of inflation targeting (4% ± 2%).

VAID IAS:UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

Statement (d) is incorrect. The WPI is calculated and released by the **Office of the Economic Adviser (OEA)**, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), under the **Ministry of Commerce & Industry**. The CPI is calculated by the National Statistical Office (NSO).

व्याख्या- कथन (b) **सही** है। भारत में **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)** उत्पादक या थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। WPI की गणना के लिए **वर्तमान आधार वर्ष** वास्तव में **2011-12** है, और WPI बास्केट में सबसे अधिक भार **विनिर्मित उत्पादों** को (लगभग 64.23%) दिया गया है, जिसके बाद प्राथमिक वस्तुएँ और ईंधन एवं बिजली आते हैं।

कथन (a) गलत है। WPI खुदरा स्तर पर नहीं, बल्कि थोक स्तर पर कीमतों को ट्रैक करता है। **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** खुदरा स्तर पर औसत मूल्य स्तर में बदलाव को दर्शाता है।

कथन (c) गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (4% ± 2%) के अपने प्राथमिक मौद्रिक नीति उद्देश्य के लिए मुख्य माप के रूप में संयुक्त **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-C)** को अपनाया है।

कथन (d) गलत है। WPI की गणना और प्रकाशन **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)** के तहत **आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA)**, **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** द्वारा किया जाता है। CPI की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा की जाती है।

3. Answer- (a)

Explanation- Statement 1 is correct. Cash Reserve Ratio (CRR) is the share of a bank's Net Demand and Time Liabilities (NDTL) that it has to maintain with the RBI in the form of cash. An increase in CRR means banks have to hold more cash with the RBI, reducing the amount available for lending. This reduces the money supply and credit creation in the economy, which is a key measure to control inflation.

Statement 2 is correct. **Statutory Liquidity Ratio (SLR)** is the minimum percentage of deposits (NDTL) that a commercial bank has to maintain in the form of liquid assets. These liquid assets can be cash, gold, or unencumbered approved securities (mostly government securities), ensuring the bank's solvency and stability.

Statement 3 is incorrect. Open Market Operations (OMO), which involve the buying and selling of government securities, are indeed used by the RBI to manage liquidity. However, the primary effect of OMO is on the **money supply and long-term interest rates**. **Liquidity Adjustment Facility (LAF)**, which includes the **Repo Rate** and **Reverse Repo Rate**, is the primary tool used by the RBI to manage **short-term liquidity** and signal the monetary policy stance, thereby influencing the short-term interbank rate. OMO's effect on the repo rate is indirect, not primary.

व्याख्या- कथन 1 सही है। नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बैंक की शुद्ध मांग और समय देनदारियों (NDTL) का वह हिस्सा है जिसे उसे नकदी के रूप में RBI के पास बनाए रखना होता है। CRR में वृद्धि का मतलब है कि बैंकों को RBI के पास अधिक नकदी रखनी होगी, जिससे ऋण देने के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाएगी। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ऋण निर्माण को कम करता है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक प्रमुख उपाय है।

कथन 2 सही है। सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) जमा (NDTL) का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंक को तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना होता है। ये तरल परिसंपत्तियाँ नकद, सोना, या अप्रतिबंधित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियाँ) हो सकती हैं, जो बैंक की शोधन क्षमता और स्थिरता सुनिश्चित करती हैं।

VAID IAS-IPSC (OSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

कथन 3 गलत है। खुले बाजार परिचालन (OMO), जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है, का उपयोग वास्तव में RBI द्वारा तरलता को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। हालांकि, OMO का प्राथमिक प्रभाव **मुद्रा आपूर्ति और दीर्घकालिक ब्याज दरों** पर होता है। **तरलता समायोजन सुविधा (LAF)**, जिसमें **रेपो दर** और **रिवर्स रेपो दर** शामिल है, मुख्य रूप से **अल्पकालिक तरलता** का प्रबंधन करने और मौद्रिक नीति के रुख को संकेत देने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण है, जिससे अल्पकालिक अंतर-बैंक दर प्रभावित होती है। रेपो दर पर OMO का प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है, प्राथमिक नहीं।

4. Answer- (d)

Explanation- Statement 1 is incorrect. Receipts from the sale of government equity in PSUs, known as **Disinvestment Receipts**, are classified as **Capital Receipts** because they result in a reduction of government assets. Revenue receipts neither create a liability nor reduce assets.

Statement 2 is correct. Revenue Expenditure includes all expenditure that does not result in the creation of assets or the reduction of liabilities. **Interest payments** on past loans and **subsidies** are classic examples of revenue expenditure.

Statement 3 is correct. Fiscal Deficit is defined as the excess of total expenditure (both revenue and capital) over total receipts (both revenue and capital) **excluding borrowings**. Since it represents the gap in the government's finances that needs to be covered by borrowing, the Fiscal Deficit is, by definition, the **total borrowing requirement** of the government.

Statement 4 is incorrect. Goods and Services Tax (GST) is an **Indirect Tax**, which is generally considered **regressive** because it is levied uniformly on a good or service regardless of the consumer's income level, meaning it takes a larger percentage of income from low-income earners than from high-income earners. While higher GST rates on luxury goods introduce an element of progressivity in consumption, the tax itself remains a type of indirect tax and is primarily classified as regressive in its overall effect on income distribution compared to Direct Taxes (like Income Tax).

व्याख्या- कथन 1 गलत है। PSUs में सरकारी इक्विटी की बिक्री से प्राप्तियों, जिन्हें **विनिवेश प्राप्तियां** कहा जाता है, को **पूंजीगत प्राप्तियों** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे सरकारी परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। राजस्व प्राप्तियाँ न तो कोई देनदारी उत्पन्न करती हैं और न ही परिसंपत्तियों को कम करती हैं।

कथन 2 सही है। राजस्व व्यय में वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण या देनदारियों में कमी नहीं होती है। पिछले ऋणों पर **ब्याज भुगतान** और **सब्सिडी** राजस्व व्यय के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

कथन 3 सही है। राजकोषीय घाटा कुल प्राप्तियों (राजस्व और पूंजी दोनों) पर कुल व्यय (राजस्व और पूंजी दोनों) के अधिशेष के रूप में परिभाषित किया जाता है, **उधार को छोड़कर**। चूंकि यह सरकार के वित्त में उस अंतर को दर्शाता है जिसे उधार लेकर पूरा करने की आवश्यकता होती है, इसलिए राजकोषीय घाटा, परिभाषा के अनुसार, सरकार की **कुल उधार आवश्यकता** है।

कथन 4 गलत है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक **अप्रत्यक्ष कर** है, जिसे आम तौर पर **प्रतिगामी** माना जाता है क्योंकि यह उपभोक्ता के आय स्तर की परवाह किए बिना किसी वस्तु या सेवा पर समान रूप से लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च आय वालों की तुलना में कम आय वालों से आय का एक बड़ा प्रतिशत लेता है। जबकि विलासिता की वस्तुओं पर उच्च GST दरें उपभोग में प्रगतिशीलता का एक तत्व लाती हैं, यह कर स्वयं अप्रत्यक्ष कर का एक प्रकार बना रहता है और आय वितरण पर इसके समग्र प्रभाव में प्रत्यक्ष करों (जैसे आयकर) की तुलना में मुख्य रूप से प्रतिगामी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

VAID IAS UPPCS (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

5. Answer- (a)

Explanation- 1. **Net National Product (NNP) (Incorrectly Matched):** NNP is calculated as **GNP minus Depreciation (Consumption of Fixed Capital)**. The formula given (GNP minus total indirect taxes and subsidies) is the calculation for National Income at **Factor Cost** from National Income at **Market Price**.

2. **Per Capita Income (PCI) (Correctly Matched):** PCI is a simple measure of the average income per person in a given region. It is correctly calculated as **National Income (or NNP at Factor Cost) divided by the total population** of the country.

3. **Gini Coefficient (Incorrectly Matched):** The Gini Coefficient is a measure of **income inequality** (or wealth inequality). It ranges from 0 to 1 (or 0% to 100%). A value of **0** represents perfect **equality** (everyone has the same income), and a value of **1** (or 100%) represents perfect **inequality** (one person has all the income). Therefore, a **higher value** indicates **more inequality** or a less equitable distribution, not a more equitable one.

Therefore, only Pair 2 is correctly matched.

व्याख्या- 1. **निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) (गलत सुमेलित):** NNP की गणना **GNP घटा मूल्यह्रास (स्थिर पूंजी की खपत)** के रूप में की जाती है। दिया गया सूत्र (GNP घटा कुल अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी) **बाजार मूल्य** पर राष्ट्रीय आय से **कारक लागत** पर राष्ट्रीय आय की गणना है।

2. **प्रति व्यक्ति आय (PCI) (सही सुमेलित):** PCI किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत आय का एक सरल माप है। इसकी गणना सही ढंग से **राष्ट्रीय आय (या कारक लागत पर NNP) को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके** की जाती है।

3. **गिनी गुणांक (गलत सुमेलित):** गिनी गुणांक **आय असमानता** (या धन असमानता) का एक माप है। यह 0 से 1 तक (या 0% से 100% तक) होता है। **0** का मान पूर्ण **समानता** (हर किसी की आय समान है) का प्रतिनिधित्व करता है, और **1** (या 100%) का मान पूर्ण **असमानता** (एक व्यक्ति के पास सारी आय है) का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, एक **उच्च मान अधिक असमानता** या कम न्यायसंगत वितरण को इंगित करता है, न कि अधिक न्यायसंगत वितरण को।

इसलिए, केवल युग्म 2 सही सुमेलित है।

6. Answer- (c)

1. **Explanation- Correct. Crowding Out** occurs when the government borrows heavily from the open market. This increases the demand for loanable funds, pushing up the market interest rates. Higher interest rates make it more expensive for private companies to borrow and invest, thereby "crowding out" private investment.
2. **Correct.** The **FRBM Act** (enacted in 2003) sets targets for deficit reduction (both Revenue Deficit and Fiscal Deficit) and aims to bring greater transparency and institutionalize prudence in the conduct of fiscal policy.
3. **Correct. Twin Deficits** (or Double Deficits) is a macro-economic concept referring to the simultaneous occurrence of two deficits: the **Fiscal Deficit** (government budget deficit) and the **Current Account Deficit (CAD)** (trade deficit plus net income/transfers).
4. **Correct.** The **Repo Rate** is the benchmark short-term interest rate set by the RBI. A high Repo Rate increases the cost of funds for banks, which in turn leads to higher interest rates across

VAID IAS:UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

the economy. Since the government borrows from the market through the issuance of bonds, the overall increase in market interest rates due to a high Repo Rate will increase the coupon rate on new government bonds, thus increasing the **cost of government borrowing**.

5. **Incorrect.** A high **Current Account Deficit (CAD)** typically requires corrective measures related to the exchange rate, trade policy, or capital flows management, which are under the purview of both the government and the RBI. While the RBI may respond, the primary tool to directly influence domestic liquidity and control inflation (which is the main function of CRR) is not necessitated *directly* by CAD. A rise in CAD might prompt a broader monetary tightening, but increasing CRR is one of many tools and is a less direct response to CAD compared to managing foreign exchange reserves or intervening in the forex market.
   Therefore, 1, 2, 3, and 4 are correct.

व्याख्या-

1. **सही। क्राउडिंग आउट** तब होता है जब सरकार खुले बाजार से भारी उधार लेती है। इससे उधार योग्य निधियों की मांग बढ़ जाती है, जिससे बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। उच्च ब्याज दरें निजी कंपनियों के लिए उधार लेना और निवेश करना अधिक महंगा बना देती हैं, जिससे निजी निवेश "बाहर हो जाता है"।
2. **सही। FRBM अधिनियम** (2003 में अधिनियमित) घाटा कम करने (राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों) के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और राजकोषीय नीति के संचालन में अधिक पारदर्शिता लाने और विवेक को संस्थागत बनाने का लक्ष्य रखता है।
3. **सही।** दोहरा घाटा एक व्यापक आर्थिक अवधारणा है जो दो घाटे की एक साथ घटना को संदर्भित करती है: **राजकोषीय घाटा** (सरकारी बजट घाटा) और **चालू खाता घाटा (CAD)** (व्यापार घाटा प्लस शुद्ध आय/हस्तांतरण)।
4. **सही। रेपो दर** RBI द्वारा निर्धारित बेंचमार्क अल्पकालिक ब्याज दर है। एक उच्च रेपो दर बैंकों के लिए धन की लागत बढ़ाती है, जिससे बदले में पूरे अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। चूंकि सरकार बॉन्ड जारी करने के माध्यम से बाजार से उधार लेती है, एक उच्च रेपो दर के कारण बाजार ब्याज दरों में समग्र वृद्धि नए सरकारी बॉन्ड पर कूपन दर को बढ़ाएगी, इस प्रकार **सरकारी उधार की लागत** में वृद्धि होगी।
5. **गलत।** एक उच्च **चालू खाता घाटा (CAD)** के लिए आमतौर पर विनिमय दर, व्यापार नीति, या पूंजी प्रवाह प्रबंधन से संबंधित सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है, जो सरकार और RBI दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जबकि RBI प्रतिक्रिया दे सकता है, घरेलू तरलता को सीधे प्रभावित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्राथमिक उपकरण (जो CRR का मुख्य कार्य है) CAD द्वारा *सीधे* आवश्यक नहीं होता है। CAD में वृद्धि व्यापक मौद्रिक सख्ती को प्रेरित कर सकती है, लेकिन CRR बढ़ाना कई उपकरणों में से एक है और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन या विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की तुलना में CAD के लिए कम प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया है।
   इसलिए, 1, 2, 3 और 4 सही हैं।

7. Answer- (a)

Explanation- Assertion (A) is True. Cost-Push Inflation is caused by a decrease in aggregate supply (e.g., due to rising oil prices or wage rates). If the central bank attempts to control this inflation by raising interest rates (a contractionary monetary policy), it will primarily reduce **Aggregate Demand**. Since the problem is on the supply side, reducing demand will only lead to lower output and higher unemployment, exacerbating the state of stagnation (low growth, high

VAID ICS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

unemployment) associated with **stagflation**, without significantly tackling the root cause of the inflation (the supply shock).

Reason (R) is True and is the Correct Explanation of A. The core mechanism of monetary policy is to influence Aggregate Demand through interest rates. Raising rates (as stated in R) reduces borrowing and spending, thus lowering Demand. However, this action does not directly address the *cause* of cost-push inflation, which is the high cost of production/inputs (as stated in R). With persistent high costs and now reduced demand, firms are forced to cut production, which increases unemployment and worsens the "stagnation" component mentioned in Assertion (A). Therefore, Reason (R) correctly explains why the use of monetary policy alone can be counterproductive in a cost-push inflation scenario.

व्याख्या- अभिकथन (A) सही है। लागत-जन्य मुद्रास्फीति समग्र आपूर्ति में कमी के कारण होती है (उदाहरण के लिए, बढ़ते तेल की कीमतों या मजदूरी दरों के कारण)। यदि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाकर (एक संकुचनकारी मौद्रिक नीति) इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो यह मुख्य रूप से **कुल मांग** को कम करेगा। चूंकि समस्या आपूर्ति पक्ष पर है, मांग को कम करने से केवल कम उत्पादन और उच्च बेरोजगारी होगी, जिससे **मुद्रास्फीतिजनित मंदी** (कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी) से जुड़ी ठहराव की स्थिति और बिगड़ जाएगी, बिना मुद्रास्फीति के मूल कारण (आपूर्ति झटका) से महत्वपूर्ण रूप से निपटे।

कारण (R) सही है और अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। मौद्रिक नीति का मुख्य तंत्र ब्याज दरों के माध्यम से कुल मांग को प्रभावित करना है। दरों को बढ़ाने से (जैसा कि R में कहा गया है) उधार लेना और खर्च करना कम हो जाता है, जिससे मांग कम हो जाती है। हालांकि, यह कार्रवाई लागत-जन्य मुद्रास्फीति के *कारण* को सीधे संबोधित नहीं करती है, जो उत्पादन/आगतों की उच्च लागत है (जैसा कि R में कहा गया है)। लगातार उच्च लागत और अब कम मांग के साथ, फर्म उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर होती हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और अभिकथन (A) में उल्लिखित "ठहराव" घटक खराब होता है। इसलिए, कारण (R) सही ढंग से बताता है कि लागत-जन्य मुद्रास्फीति के परिदृश्य में अकेले मौद्रिक नीति का उपयोग क्यों प्रतिकूल हो सकता है।

8. Answer- (a)

Explanation-

A. Income Method (2): This method estimates national income by summing up all the **factor payments** made to the factors of production—**Wages** (for labour), **Rent** (for land), **Interest** (for capital), and **Profits** (for entrepreneurship).

B. Expenditure Method (3): This method calculates national income by summing the final **expenditure** on domestically produced goods and services by different sectors: **Consumption** (C), **Investment** (I), **Government Spending** (G), and **Net Exports** (X-M).

C. Production (Value-Added) Method (1): This method calculates the **Net Value Added (NVA) at Factor Cost** by all producing enterprises within the domestic territory, effectively summing up the monetary value of all goods and services produced.

D. National Income at Factor Cost (4): National Income is officially defined as **Net National Product (NNP) at Factor Cost**. It is derived from NNP at Market Price by subtracting **Indirect Taxes** and adding **Subsidies** (NNP_{FC} = NNP_{MP} - Indirect Taxes + subsidies).

VAIDICS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

व्याख्या-

A. आय विधि (2): यह विधि उत्पादन के कारकों को किए गए सभी **कारक भुगतानों—मजदूरी** (श्रम के लिए), **किराया** (भूमि के लिए), **ब्याज** (पूंजी के लिए), और **लाभ** (उद्यम के लिए)—को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है।

B. व्यय विधि (3): यह विधि विभिन्न क्षेत्रों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए अंतिम **व्यय** को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करती है: **उपभोग** (C), **निवेश** (I), **सरकारी व्यय** (G), और **शुद्ध निर्यात** (X-M)।

C. उत्पादन (मूल्य-वर्धित) विधि (1): यह विधि घरेलू सीमा के भीतर सभी उत्पादन करने वाले उद्यमों द्वारा **कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वर्धित (NVA)** की गणना करती है, जो उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ती है।

D. कारक लागत पर राष्ट्रीय आय (4): राष्ट्रीय आय को आधिकारिक तौर पर **कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद** (NNP_{FC}) के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे बाजार मूल्य पर NNP में से **अप्रत्यक्ष करों** को घटाकर और **सब्सिडी** को जोड़कर प्राप्त किया जाता है ($NNP_{FC} = NNP_{MP}$ - अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी).

9. Answer- (b)

Explanation- Statement (b) is **incorrect**. The Brundtland Report, titled *Our Common Future*, provided the foundational concept and definition of sustainable development. While it strongly linked economic development with environmental protection and emphasized the need for a shift in development pathways, the idea that economic growth must be **fully decoupled** from environmental degradation is a more recent and stringent concept (e.g., in the context of circular economy and post-SDG discussions) that goes beyond the principles primarily articulated in the 1987 report. The report called for economic development with a view to environmental sustainability, not necessarily a complete, immediate decoupling as an introduced principle.

Statement (a) is correct. Intergenerational equity is a core principle. Statement (c) is correct. The report highlighted that poverty is a major cause and effect of global environmental problems. Statement (d) is correct. The report is famous for providing the classic definition of sustainable development.

व्याख्या- कथन (b) **गलत** है। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, जिसका शीर्षक *हमारा साझा भविष्य* है, ने सतत विकास की मूलभूत अवधारणा और परिभाषा प्रदान की। जबकि इसने आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ दृढ़ता से जोड़ा और विकास के मार्गों में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, यह विचार कि आर्थिक वृद्धि को पर्यावरणीय क्षरण से **पूरी तरह से अलग** किया जाना चाहिए, एक अधिक हालिया और कठोर अवधारणा है (उदाहरण के लिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था और SDG के बाद की चर्चाओं के संदर्भ में) जो मुख्य रूप से 1987 की रिपोर्ट में व्यक्त किए गए सिद्धांतों से परे है। रिपोर्ट में पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का आह्वान किया गया था, न कि जरूरी तौर पर एक पेश किए गए सिद्धांत के रूप में पूर्ण, तत्काल अलगाव का।

कथन (a) सही है। अंतर-पीढ़ीगत समता एक मूल सिद्धांत है। कथन (c) सही है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि गरीबी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का एक प्रमुख कारण और प्रभाव है। कथन (d) सही है। यह रिपोर्ट सतत विकास की उत्कृष्ट परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है।

10. Answer- (c)

Explanation- Statement 1 is correct. A key provision of the original **FRBM Act** (2003) restricted the government from borrowing directly from the Reserve Bank of India (RBI) after April 1, 2006 (except under exceptional circumstances). This measure was crucial because direct borrowing (also known as 'monetization of the deficit') leads to an immediate increase in the money supply,

VAID ICS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

which is highly inflationary and directly undermines the RBI's price stability mandate, thus aligning fiscal policy with long-term price stability.

Statement 2 is correct. High government borrowing means the government enters the market to raise a large amount of funds, increasing the overall demand for funds. This increased demand for loanable funds puts **upward pressure on market interest rates**. If the RBI is simultaneously pursuing a low-interest rate regime (an easy monetary policy), the large-scale government borrowing can counter this effort, leading to 'crowding out' and making the monetary policy less effective.

व्याख्या- कथन 1 सही है। मूल **FRBM अधिनियम** (2003) का एक प्रमुख प्रावधान सरकार को 1 अप्रैल, 2006 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से सीधे उधार लेने से प्रतिबंधित करता है (असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर)। यह उपाय महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रत्यक्ष उधार (जिसे 'घाटे का मुद्रीकरण' भी कहा जाता है) से मुद्रा आपूर्ति में तत्काल वृद्धि होती है, जो अत्यधिक मुद्रास्फीतिजनक है और सीधे RBI के मूल्य स्थिरता जनादेश को कमजोर करता है, इस प्रकार राजकोषीय नीति को दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता के साथ संरेखित करता है।

कथन 2 सही है। उच्च सरकारी उधार का मतलब है कि सरकार बड़ी मात्रा में धन जुटाने के लिए बाजार में प्रवेश करती है, जिससे धन की समग्र मांग बढ़ जाती है। उधार योग्य निधियों की यह बढ़ी हुई मांग **बाजार ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव** डालती है। यदि RBI समवर्ती रूप से कम-ब्याज दर व्यवस्था (एक आसान मौद्रिक नीति) अपना रहा है, तो बड़े पैमाने पर सरकारी उधार इस प्रयास का प्रतिकार कर सकता है, जिससे 'क्राउडिंग आउट' हो सकता है और मौद्रिक नीति कम प्रभावी हो सकती है।

11.

Answer- (c)

Explanation- Statement (c) is correct. A **Progressive Tax** is a tax where the tax rate increases as the taxable amount (income) increases. This design ensures that the wealthy pay a higher proportion of their income in tax, thereby promoting vertical equity and reducing income inequality. The **Income Tax** in India is an example of a progressive tax.

Statement (a) describes a **Proportional Tax** in terms of rate constancy, but the second part ("tax burden is felt more by lower-income groups") describes a **Regressive Tax** in effect. Statement (b) describes a **Regressive Tax**. Statement (d) describes the nature of a **Direct Tax** (incidence and impact are on the same person), but not the progressive nature itself.

व्याख्या- कथन (c) सही है। प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जहाँ कर योग्य राशि (आय) बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है। यह डिज़ाइन सुनिश्चित करता है कि धनी लोग अपनी आय का एक उच्च अनुपात कर के रूप में भुगतान करें, जिससे ऊर्ध्वाधर इक्विटी को बढ़ावा मिलता है और आय असमानता कम होती है। भारत में **आयकर** एक प्रगतिशील कर का एक उदाहरण है।

कथन (a) दर की स्थिरता के संदर्भ में एक समानुपातिक कर का वर्णन करता है, लेकिन दूसरा भाग ("कर का बोझ कम आय वाले समूहों द्वारा अधिक महसूस किया जाता है") प्रभाव में एक प्रतिगामी कर का वर्णन करता है।

कथन (b) एक प्रतिगामी कर का वर्णन करता है।

कथन (d) प्रत्यक्ष कर की प्रकृति का वर्णन करता है (घटना और प्रभाव एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं), लेकिन प्रगतिशील प्रकृति का स्वयं नहीं।

VAID ICS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

12.

Answer- (c)

Explanation-

1. **Correct:** High oil prices increase the cost of inputs for various industries (transportation, manufacturing, etc.), which firms pass on to consumers by raising prices, fitting the definition of Cost-Push Inflation.
2. **Correct:** The wage-price spiral describes a scenario where inflation expectations become self-fulfilling, leading to a persistent increase in prices. This is the mechanism underlying **Built-in Inflation** (or Inertial Inflation).
3. **Correct:** Lowering the Repo Rate reduces the cost of borrowing, which boosts consumption and investment, increasing Aggregate Demand. If supply cannot keep pace, this results in Demand-Pull Inflation.
4. **Incorrect: Stagflation** is the combination of **Stagnation** (low/slow or negative economic growth, high unemployment) and **high Inflation**. High output growth is the **opposite** of stagnation.

Therefore, three of the four factors and their corresponding effects/situations are correctly matched (1, 2, and 3).

व्याख्या-

1. **सही:** उच्च तेल कीमतें विभिन्न उद्योगों (परिवहन, विनिर्माण, आदि) के लिए आगतों की लागत को बढ़ाती हैं, जिसे फर्म कीमतों में वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर डालती हैं, जो लागत-जन्य मुद्रास्फीति की परिभाषा के अनुरूप है।
2. **सही:** मजदूरी-मूल्य सर्पिल एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जहाँ मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ स्व-पूर्तिदायक बन जाती हैं, जिससे कीमतों में लगातार वृद्धि होती है। यह **अंतर्निहित मुद्रास्फीति** (या जड़त्वीय मुद्रास्फीति) के अंतर्निहित तंत्र है।
3. **सही:** रेपो दर को कम करने से उधार लेने की लागत कम हो जाती है, जिससे उपभोग और निवेश को बढ़ावा मिलता है, कुल मांग बढ़ जाती है। यदि आपूर्ति गति नहीं रख पाती है, तो इसका परिणाम मांग-जनित मुद्रास्फीति होता है।
4. **गलत: मुद्रास्फीतिजनित मंदी ठहराव** (कम/धीमा या नकारात्मक आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी) और **उच्च मुद्रास्फीति** का संयोजन है। उच्च उत्पादन वृद्धि ठहराव के **विपरीत** है।

इसलिए, चार में से तीन कारक और उनके संबंधित प्रभाव/स्थितियाँ सही सुमेलित हैं (1, 2, और 3)।

13.

Answer- (b)

Explanation- Statement 1 is correct. The **Repo Rate** is the main signaling rate for the RBI's monetary policy. It is the rate at which commercial banks can borrow money from the RBI by selling their government securities with an agreement to repurchase them later (short-term borrowing).

Statement 2 is correct. The **Cash Reserve Ratio (CRR)** is the portion of a bank's deposits (NDTL) that it must keep with the RBI. Banks **do not earn any interest** on the CRR balance kept with the RBI, making it a powerful tool to control liquidity.

VAID IAS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

Statement 3 is incorrect. The **Marginal Standing Facility (MSF)** is an emergency facility for banks to borrow funds overnight when inter-bank liquidity dries up. To discourage routine use and to maintain the Repo Rate as the benchmark, the MSF rate is typically kept at the **upper end of the interest rate corridor** (usually **higher** than the Repo Rate).
Statement 4 is **correct**. **Open Market Operations (OMO)**, which are outright sales or purchases of government securities, are used for the **long-term management** of liquidity and money supply (i.e., permanent injection/absorption). In contrast, the **Liquidity Adjustment Facility (LAF)**, which includes Repo and Reverse Repo, is used for **day-to-day/temporary** liquidity management.
Therefore, statements 1, 2, and 4 are correct.
व्याख्या- कथन 1 सही है। रेपो दर RBI की मौद्रिक नीति के लिए मुख्य संकेत दर है। यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को बाद में पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ बेचकर अल्पकालिक धन उधार ले सकते हैं (अल्पकालिक उधार)।
कथन 2 सही है। नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बैंक की जमा राशि (NDTL) का वह हिस्सा है जिसे उसे RBI के पास रखना होता है। बैंक RBI के पास रखे गए CRR शेष पर **कोई ब्याज अर्जित नहीं करते हैं**, जिससे यह तरलता को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है।
कथन 3 गलत है। सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) बैंकों के लिए एक आपातकालीन सुविधा है ताकि अंतर-बैंक तरलता सूख जाने पर रातोंरात धन उधार लिया जा सके। इसके नियमित उपयोग को हतोत्साहित करने और रेपो दर को बेंचमार्क के रूप में बनाए रखने के लिए, MSF दर को आमतौर पर **ब्याज दर गलियारे के ऊपरी सिरे** पर (आमतौर पर रेपो दर से **अधिक**) रखा जाता है।
कथन 4 सही है। खुले बाजार परिचालन (OMO), जो सरकारी प्रतिभूतियों की पूर्ण बिक्री या खरीद हैं, का उपयोग तरलता और मुद्रा आपूर्ति के **दीर्घकालिक प्रबंधन** (अर्थात्, स्थायी रूप से डालना/अवशोषण) के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, **तरलता समायोजन सुविधा (LAF)**, जिसमें रेपो और रिवर्स रेपो शामिल हैं, का उपयोग **दिन-प्रतिदिन/अस्थायी** तरलता प्रबंधन के लिए किया जाता है।
इसलिए, कथन 1, 2 और 4 सही हैं।

14.
Answer- (a)
Explanation- Statement I is **correct**. The informal sector in India is vast and poorly documented, making GDP estimation a challenge.
Statement II is **correct**. The **Production (Value-Added) Method** involves summing up the Net Value Added (NVA) at Factor Cost for all producing units in the economy. This requires firms to report their final output and, crucially, their intermediate consumption (inputs used in production) accurately. Informal or unorganized units (like small, unregistered shops or street vendors) typically do not maintain proper books of accounts, making it extremely difficult to obtain the necessary **detailed and accurate data** on intermediate consumption and value of output. This lack of data directly causes the "significant challenge" mentioned in Statement I.
Therefore, both statements are correct, and Statement II provides the correct **technical explanation** for the challenge described in Statement I.

VAID ICS UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

व्याख्या- कथन I **सही** है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र विशाल और खराब तरीके से प्रलेखित है, जिससे GDP अनुमान एक चुनौती बन जाता है।

कथन II **सही** है। **उत्पादन (मूल्य-वर्धित) विधि** में अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक इकाइयों के लिए कारक लागत पर निवल मूल्य वर्धित (NVA) को जोड़ना शामिल है। इसके लिए फर्मों को अपने अंतिम उत्पादन के मूल्य और, महत्वपूर्ण रूप से, अपने मध्यवर्ती उपभोग (उत्पादन में उपयोग किए गए आगत) की सटीक रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। अनौपचारिक या असंगठित इकाइयाँ (जैसे छोटी, अपंजीकृत दुकानें या सड़क विक्रेता) आमतौर पर खातों की उचित किताबें नहीं रखती हैं, जिससे मध्यवर्ती उपभोग और उत्पादन के मूल्य पर आवश्यक **विस्तृत और सटीक डेटा** प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। डेटा की यह कमी सीधे कथन I में वर्णित "महत्वपूर्ण चुनौती" का कारण बनती है।

इसलिए, दोनों कथन सही हैं, और कथन II, कथन I में वर्णित चुनौती के लिए सही **तकनीकी व्याख्या** प्रदान करता है।

15.

Answer- (a)

Explanation- Revenue Receipts are receipts that **neither create a liability nor cause a reduction in the assets** of the government.

1. **Proceeds from a new PSU issuance of shares (Incorrect):** This is a capital receipt (disinvestment) as it reduces the government's assets (ownership/equity in the PSU). *Note: The question specifies 'new PSU issuance', which is typically a capital receipt for the government unless the government is acting as an intermediary.*
2. **Recovery of loans and advances (Incorrect):** This is a **Capital Receipt** because it reduces the government's assets (the outstanding loan/advance).
3. **Taxes on income (Direct Tax) (Correct):** Taxes are revenue receipts as they neither create a liability nor reduce assets.
4. **Goods and Services Tax (GST) collection (Indirect Tax) (Correct):** Taxes are revenue receipts as they neither create a liability nor reduce assets.
5. **Borrowings from the market (Incorrect):** This is a **Capital Receipt** because it **creates a liability** (the government owes money to the lenders).

Therefore, only two receipts (3 and 4: Taxes) are classified as Revenue Receipts.

व्याख्या- व्याख्या- राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो **न तो कोई देनदारी बनाती हैं और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं।**

1. **किसी नए सार्वजनिक उपक्रम द्वारा शेयर जारी करने से प्राप्त आय (गलत):** यह एक पूँजीगत प्राप्ति (विनिवेश) है क्योंकि यह सरकार की परिसंपत्तियों (सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व/इक्विटी) को कम करती है। नोट: प्रश्न में 'नए सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी' शब्द का उल्लेख है, जो आमतौर पर सरकार के लिए एक पूँजीगत प्राप्ति होती है, जब तक कि सरकार मध्यस्थ के रूप में कार्य न कर रही हो।
2. **ऋणों और अग्रिमों की वसूली (गलत):** यह एक पूँजीगत प्राप्ति है क्योंकि यह सरकार की परिसंपत्तियों (बकाया ऋण/अग्रिम) को कम करती है।
3. **आय पर कर (प्रत्यक्ष कर) (सही):** कर राजस्व प्राप्तियाँ हैं क्योंकि वे न तो कोई देनदारी बनाते हैं और न ही परिसंपत्तियों को कम करते हैं।
4. **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह (अप्रत्यक्ष कर) (सही):** कर राजस्व प्राप्तियाँ हैं क्योंकि वे न तो कोई देनदारी बनाते हैं और न ही परिसंपत्तियों को कम करते हैं।

VAID ICS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

5. **बाज़ार से उधार (गलत):** यह एक पूँजीगत प्राप्ति है क्योंकि यह एक दायित्व उत्पन्न करती है (सरकार ऋणदाताओं को धन देती है)।

इसलिए, केवल दो प्राप्तियाँ (3 और 4: कर) राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

16.

Answer- (b)

Explanation- Statement 1 is incorrect. A sustained rise in **Per Capita Income** (PCI), while an indicator of economic growth, does not inherently guarantee a reduction in income inequality or poverty. The benefits of growth can be concentrated among a small percentage of the population, leading to what is often termed 'non-inclusive growth'. For instance, a country can have high PCI but significant wealth disparity, making the average misleading for the majority of the population. Therefore, economic growth, being a quantitative measure, is not sufficient to ensure qualitative improvement like reduced inequality.

Statement 2 is correct. Economic Development is indeed a qualitative and multidimensional concept. It goes beyond mere quantitative increases in output (growth) to focus on improvements in the quality of life, which includes better health outcomes, higher educational attainment, lower levels of inequality, and reduced regional disparities. The Human Development Index (HDI) is a prime example of an indicator designed to capture these multidimensional aspects of development. Therefore, development entails structural changes and better living standards, not just an increase in income.

व्याख्या- कथन 1 गलत है। प्रति व्यक्ति आय (PCI) में निरंतर वृद्धि, हालांकि आर्थिक संवृद्धि का एक संकेतक है, लेकिन यह आय असमानता या गरीबी में कमी की स्वाभाविक रूप से गारंटी नहीं देता है। विकास का लाभ जनसंख्या के एक छोटे प्रतिशत तक ही केंद्रित हो सकता है, जिससे अक्सर इसे 'गैर-समावेशी विकास' कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी देश में उच्च PCI हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण धन असमानता हो सकती है, जिससे औसत आय आबादी के अधिकांश हिस्से के लिए भ्रामक हो जाती है। इसलिए, आर्थिक संवृद्धि, एक मात्रात्मक माप होने के कारण, असमानता में कमी जैसे गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कथन 2 सही है। आर्थिक विकास वास्तव में एक गुणात्मक और बहुआयामी अवधारणा है। यह केवल उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि (वृद्धि) से परे जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, उच्च शैक्षिक उपलब्धि, असमानता का निम्न स्तर और कम क्षेत्रीय असमानताएँ शामिल हैं। मानव विकास सूचकांक (HDI) विकास के इन बहुआयामी पहलुओं को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए एक संकेतक का एक प्रमुख उदाहरण है। इसलिए, विकास में केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन और बेहतर जीवन स्तर शामिल हैं।

17.

Answer- (d)

Explanation- Sentence 1 is correct. Since the formal adoption of the flexible inflation targeting framework in 2016, the RBI has used the **CPI (Combined)** as the key inflation measure for policy decisions.

VAID ICS/UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

Sentence 2 is incorrect. WPI tracks inflation at the producer/wholesale level and only includes **goods** (commodities). **CPI tracks inflation at the retail/consumer level** and includes both **goods and services**. Therefore, CPI has a broader coverage of the economy, especially including the rapidly growing services sector.

Sentence 3 is correct. The current base year for the All India **CPI (Combined)** is indeed **2012**. The base year for the WPI is 2011-12.

Sentence 4 is incorrect. While the CPI framework uses fixed weights based on the base year consumption basket (like a Laspeyres index), the official CPI in India (like in many countries) uses a modified Laspeyres formula, but more critically, the statement is not a common fact that needs to be known at this level. The main point is that the weights are fixed. The statement about the Laspeyres index is a simplification and is not strictly accurate in the Indian context.

Sentence 5 is incorrect. **Food and beverages** have a significantly **higher weight in the CPI basket** (around 45-50%) because they constitute a larger share of the average household's consumption expenditure, especially for the poor. In WPI, manufactured products have the highest weight, and food is a much smaller component.

Therefore, only Sentences 1 and 3 are correct.

व्याख्या- कथन 1 सही है। 2016 में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को औपचारिक रूप से अपनाने के बाद से, आरबीआई ने नीतिगत फैसलों के लिए प्रमुख मुद्रास्फीति माप के रूप में **CPI (संयुक्त)** का उपयोग किया है।

कथन 2 गलत है। WPI उत्पादक/थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है और इसमें केवल **वस्तुएं** (कमोडिटीज) शामिल होती हैं। **CPI खुदरा/उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है** और इसमें **वस्तुएं और सेवाएं दोनों** शामिल होती हैं। इसलिए, CPI का कवरेज अर्थव्यवस्था में व्यापक है, खासकर तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र को शामिल करते हुए।

कथन 3 सही है। अखिल भारतीय **CPI (संयुक्त)** के लिए वर्तमान आधार वर्ष वास्तव में **2012** है। WPI के लिए आधार वर्ष 2011-12 है।

कथन 4 गलत है। यद्यपि CPI ढांचा आधार वर्ष खपत टोकरी के आधार पर निश्चित भार का उपयोग करता है (जैसे लासपेयर्स सूचकांक), भारत में आधिकारिक CPI (कई देशों की तरह) एक संशोधित लासपेयर्स सूत्र का उपयोग करता है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण रूप से, यह कथन एक सामान्य तथ्य नहीं है जिसे इस स्तर पर जानने की आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि भार निश्चित हैं। लासपेयर्स सूचकांक के बारे में कथन एक सरलीकरण है और भारतीय संदर्भ में सख्ती से सटीक नहीं है।

कथन 5 गलत है। **खाद्य और पेय पदार्थों** का CPI टोकरी में **काफी अधिक भार** (लगभग 45-50%) होता है क्योंकि वे औसत घरेलू उपभोग व्यय का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, खासकर गरीबों के लिए। WPI में, विनिर्मित उत्पादों का भार सबसे अधिक होता है, और भोजन एक बहुत छोटा घटक है।

इसलिए, केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

18.

Answer- (c)

Explanation- Statement I is correct. Prolonged low interest rates encourage investors to seek higher returns in riskier assets, driving up their prices far beyond their fundamental value, thus creating **asset price bubbles**.

VAID ICS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

Statement II is correct and explains Statement I. Low borrowing costs (due to ultra-low interest rates) incentivize leveraging and risk-taking. This liquidity often flows into readily available, non-productive assets like financial instruments and real estate, inflating their prices, which is the definition of an asset price bubble. This explains the cause of the bubble mentioned in Statement I.

Statement III is incorrect. While low rates can boost consumption, the statement that this *forces* firms to increase capacity, leading to *sustainable* economic growth, is a desired outcome, but it is not a direct explanation for the **asset price bubble risk** mentioned in Statement I. Furthermore, the focus of Statement I is the *risk* of a bubble, which is a financial/investment-driven phenomenon, not a consumption-driven one.

Therefore, only Statement II is correct, and it is the correct explanation for Statement I.

व्याख्या- कथन I सही है। लंबे समय तक कम ब्याज दरें निवेशकों को जोखिम भरी परिसंपत्तियों में उच्च प्रतिफल खोजने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे उनके मूल्य उनके मौलिक मूल्य से कहीं अधिक बढ़ जाते हैं, इस प्रकार **परिसंपत्ति मूल्य बुलबुले** का निर्माण होता है।

कथन II सही है और कथन I की व्याख्या करता है। कम उधार लागत (अत्यंत कम ब्याज दरों के कारण) लीवरेजिंग और जोखिम लेने को प्रोत्साहित करती है। यह तरलता अक्सर आसानी से उपलब्ध, गैर-उत्पादक परिसंपत्तियों जैसे वित्तीय उपकरणों और रियल एस्टेट में प्रवाहित होती है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जो परिसंपत्ति मूल्य बुलबुले की परिभाषा है। यह कथन I में उल्लिखित बुलबुले के कारण की व्याख्या करता है।

कथन III गलत है। जबकि कम दरें उपभोग को बढ़ावा दे सकती हैं, यह कथन कि यह फर्मों को क्षमता बढ़ाने के लिए *मजबूर* करता है, जिससे *सतत* आर्थिक वृद्धि होती है, एक वांछित परिणाम है, लेकिन यह कथन I में उल्लिखित **परिसंपत्ति मूल्य बुलबुले के जोखिम** के लिए सीधा स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अलावा, कथन I का ध्यान बुलबुले के *जोखिम* पर है, जो एक वित्तीय/निवेश-संचालित घटना है, न कि उपभोग-संचालित।

इसलिए, केवल कथन II सही है, और यह कथन I की सही व्याख्या है।

19.

Answer- (c)

Explanation- Statement (a) is correct. Capital Receipts are receipts that either create a liability (e.g., borrowing) or cause a reduction in assets (e.g., disinvestment/recovery of loans).

Statement (b) is correct. Recovery of Loans is a Capital Receipt because it leads to a reduction in the Central Government's financial assets (the loans given out are the assets).

Statement (c) is incorrect. Direct Taxes (like Income Tax and Corporate Tax) are levied on income/profit, and their characteristic is that their **burden cannot be shifted** to another person. The person on whom the tax is legally levied must bear the cost. Taxes whose burden *can* be shifted (like GST and Excise Duty) are **Indirect Taxes**.

Statement (d) is correct. The Fiscal Deficit is financed by **Borrowings and Other Liabilities**, which are classified as Capital Receipts. This component consistently forms the largest part of the capital receipts for the government.

Therefore, statement (c) is the incorrect one.

VAID IAS UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

व्याख्या- कथन (a) सही है। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो या तो एक देनदारी पैदा करती हैं (उदाहरण के लिए, उधार लेना) या परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं (उदाहरण के लिए, विनिवेश/ऋण की वसूली)।

कथन (b) सही है। राज्य सरकारों से **ऋण की वसूली** एक पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि यह केंद्र सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों (दिए गए ऋण परिसंपत्तियां हैं) में कमी लाती है।

कथन (c) गलत है। प्रत्यक्ष कर (जैसे आयकर और कॉर्पोरेट कर) आय/लाभ पर लगाए जाते हैं, और उनकी विशेषता यह है कि उनका **बोझ दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता** है। जिस व्यक्ति पर कर कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे ही लागत वहन करनी होती है। वे कर जिनका बोझ *स्थानांतरित* किया जा सकता है (जैसे GST और उत्पाद शुल्क) **अप्रत्यक्ष कर** हैं।

कथन (d) सही है। राजकोषीय घाटा **उधार और अन्य देनदारियां** द्वारा वित्तपोषित होता है, जिन्हें पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह घटक लगातार सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है।

इसलिए, कथन (c) गलत है।

20.

Answer- (b)

Explanation- Government receipts are broadly classified into **Revenue Receipts** and **Capital Receipts**.

Revenue Receipts are those receipts that **neither** create a liability **nor** reduce assets of the government. They are generally recurring in nature.

1. **Interest receipts on loans given by the Central Government:** This is a **Non-Tax Revenue Receipt**. It does not create a liability or reduce assets. (Correct)
2. **Tax revenues like Income Tax and GST:** These are the largest component of **Tax Revenue Receipts**. They do not create a liability or reduce assets. (Correct)

Capital Receipts are those receipts that **either** create a liability **or** reduce assets of the government. They are generally non-recurring. 2. **Recovery of loans and advances:** When the government recovers a loan it had given, its assets (the loan itself) are reduced. Thus, it is a **Capital Receipt**. (Incorrect) 4. **Disinvestment proceeds:** Disinvestment is the sale of government assets (shares of Public Sector Undertakings). The sale of assets reduces the government's assets. Thus, it is a **Capital Receipt**. (Incorrect)

Therefore, only two of the above (1 and 3) are classified as Revenue Receipts.

व्याख्या- उत्तर- (b)व्याख्या- सरकारी प्राप्तियों को मोटे तौर पर **राजस्व प्राप्तियों** और **पूंजीगत प्राप्तियों** में वर्गीकृत किया जाता है।

राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो सरकार की **न तो** कोई देयता उत्पन्न करती हैं **और न ही** संपत्तियों को कम करती हैं। ये आम तौर पर आवर्ती प्रकृति की होती हैं।

1. **केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियाँ:** यह एक **गैर-कर राजस्व प्राप्ति** है। यह न तो कोई देयता उत्पन्न करता है और न ही संपत्तियों को कम करता है। (सही)
2. **आयकर और जीएसटी जैसे कर राजस्व:** ये **कर राजस्व प्राप्तियों** के सबसे बड़े घटक हैं। ये न तो कोई देयता उत्पन्न करते हैं और न ही संपत्तियों को कम करते हैं। (सही)

VAID CSJPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

पूंजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो **या तो** कोई देयता उत्पन्न करती हैं **या** सरकार की संपत्तियों को कम करती हैं। ये आम तौर पर गैर-आवर्ती होती हैं। 2. **ऋणों और अग्रिमों की वसूली:** जब सरकार अपने द्वारा दिए गए ऋण की वसूली करती है, तो उसकी संपत्ति (ऋण स्वयं) कम हो जाती है। इस प्रकार, यह एक **पूंजीगत प्राप्ति** है। (गलत) 4. **विनिवेश से प्राप्त आय:** विनिवेश सरकारी संपत्तियों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर) की बिक्री है। संपत्ति की बिक्री से सरकार की संपत्तियां कम हो जाती हैं। इस प्रकार, यह एक **पूंजीगत प्राप्ति** है। (गलत)
इसलिए, उपरोक्त में से केवल दो (1 और 3) को राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

21.

Answer- (c)

Explanation- The **International Monetary Fund (IMF)** is the international organization responsible for the creation and allocation of Special Drawing Rights (SDRs). The SDR is not a currency but an international reserve asset created by the IMF in 1969 to supplement member countries' official reserves. Its value is based on a basket of five major currencies: the US dollar, the Euro, the Chinese Yuan, the Japanese Yen, and the British Pound. The main objective of the SDR is to provide a supplementary source of liquidity for the global economy and to serve as the unit of account for the IMF and some other international organizations. Member countries can exchange SDRs for freely usable currencies among themselves or through the IMF's voluntary trading arrangements. The World Bank (WB) focuses on long-term development assistance and poverty reduction. The World Trade Organization (WTO) deals with the rules of trade between nations. The Asian Development Bank (ADB) is a regional development bank focused on Asia.
व्याख्या- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विशेष आहरण अधिकार (SDRs) के निर्माण और आवंटन के लिए जिम्मेदार है। SDR कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि 1969 में IMF द्वारा सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को पूरक करने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसका मूल्य पाँच प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है: अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। SDR का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तरलता का एक पूरक स्रोत प्रदान करना और IMF और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए खाते की इकाई के रूप में कार्य करना है। सदस्य देश आपस में या IMF की स्वैच्छिक व्यापार व्यवस्थाओं के माध्यम से SDRs को स्वतंत्र रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्राओं के लिए विनिमय कर सकते हैं। विश्व बैंक (WB) दीर्घकालिक विकास सहायता और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक (ADB) एशिया पर केंद्रित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।

22.

Answer- (b)

Explanation- The most accurate regulatory definition of a Non-Performing Asset (NPA) for commercial banks in India, as per the Reserve Bank of India (RBI) guidelines, is provided in option (b). An NPA is an asset, typically a loan or advance, for which the **principal or interest payment remained overdue for a period of more than 90 days** in respect of a term loan. For other kinds of assets, like Overdraft/Cash Credit (OD/CC) accounts, the definition is that the account remains 'out of order' for more than 90 days. Option (a) uses 180 days, which is incorrect. While

VAID ICS:UPSC (OSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

the bank management can classify an asset as 'Substandard' or 'Doubtful' (option c), the **90-day overdue rule** is the standard, objective criterion for the initial classification of a loan as an NPA. The presence or absence of collateral (option d) is a factor in the provisioning, not the initial classification as an NPA.

व्याख्या- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) की सबसे सटीक नियामक परिभाषा विकल्प (b) में दी गई है। एक NPA एक परिसंपत्ति है, आमतौर पर एक ऋण या अग्रिम, जिसके लिए सावधि ऋण के संबंध में **मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों से अधिक** की अवधि के लिए अतिदेय रहा हो। अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों, जैसे ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (OD/CC) खातों के लिए, परिभाषा यह है कि खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'अनियमित' रहता है। विकल्प (a) 180 दिनों का उपयोग करता है, जो कि गलत है। जबकि बैंक प्रबंधन एक परिसंपत्ति को 'उप-मानक' या 'संदिग्ध' (विकल्प c) के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, **90-दिन अतिदेय नियम** ऋण को NPA के रूप में प्रारंभिक वर्गीकरण के लिए मानक, वस्तुनिष्ठ मानदंड है। संपार्श्विक की उपस्थिति या अनुपस्थिति (विकल्प d) प्रावधान करने में एक कारक है, न कि NPA के रूप में प्रारंभिक वर्गीकरण में।

23.

Answer- (b)

Explanation Statement 1 is correct. The 'Make in India' initiative was launched in **September 2014** with the primary goal of encouraging companies to manufacture in India and creating a conducive environment for investment. Statement 2 is correct. The initiative originally focused on **25 key sectors**, spanning manufacturing (like automobiles, chemicals, pharmaceuticals), services (like IT, tourism), and infrastructure (like ports, railways). Statement 3 is correct. Improving India's position in the **Ease of Doing Business (EoDB)** rankings, which measure regulations that enhance or constrain business activity, has been a central pillar of the 'Make in India' initiative to make the country a global manufacturing hub. Statement 4 is incorrect. While the initiative encourages local production and there are specific public procurement policies that mandate local content for certain products, it does **not mandate a minimum level of indigenization** for **all products** across **all sectors** manufactured in India. Such blanket mandates could violate WTO obligations. Statement 5 is incorrect. The original target of raising the manufacturing sector's share in GDP to **25%** was set to be achieved by **2022** (as per the National Manufacturing Policy, 2011) and was later implicitly or explicitly carried forward, but not specifically by **2025**. The initiative's general goal is to substantially increase this share. Therefore, only three facts (1, 2, and 3) are correct.

व्याख्या- कथन 1 सही है। 'मेक इन इंडिया' पहल **सितंबर 2014** में शुरू की गई थी जिसका प्राथमिक लक्ष्य कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करना और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना था। कथन 2 सही है। यह पहल मूल रूप से विनिर्माण (जैसे ऑटोमोबाइल, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स), सेवाओं (जैसे आईटी, पर्यटन), और अवसंरचना (जैसे बंदरगाह, रेलवे) तक फैले **25 प्रमुख क्षेत्रों** पर केंद्रित थी। कथन 3 सही है। व्यापार गतिविधि को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने वाले विनियमों को मापने वाले **व्यापार सुगमता (EoDB)** रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार करना, देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल का एक केंद्रीय स्तंभ रहा है। कथन 4 गलत है। हालाँकि पहल स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और कुछ

VAID ICS-UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

उत्पादों के लिए स्थानीय सामग्री अनिवार्य करने वाली विशिष्ट सार्वजनिक खरीद नीतियाँ हैं, यह भारत में निर्मित **सभी उत्पादों** के लिए **सभी क्षेत्रों** में **स्वदेशीकरण के एक न्यूनतम स्तर को अनिवार्य नहीं** करती है। ऐसे व्यापक आदेश WTO दायित्वों का उल्लंघन कर सकते हैं। कथन 5 गलत है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को **25%** तक बढ़ाने का मूल लक्ष्य **2022** तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था (राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के अनुसार) और बाद में इसे निहित या स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाया गया, लेकिन विशेष रूप से **2025** तक नहीं। पहल का सामान्य लक्ष्य इस हिस्सेदारी को काफी बढ़ाना है। इसलिए, केवल तीन तथ्य (1, 2 और 3) सही हैं।

24.

Answer- (b)

Explanation- Statement 1 is incorrect. A current account deficit (CAD) means that the value of the sum of a country's imports of goods and services, **plus** its net income from abroad (like interest and dividends), and **plus** net current transfers (like remittances) is **greater** than the corresponding exports. The statement incorrectly *excludes* unilateral transfers and income flows. The current account is divided into: 1. Trade Balance (Goods), 2. Invisibles (Services, Income, and Transfers). All these components collectively determine the CAD. Statement 2 is correct. **Foreign Portfolio Investment (FPI)** represents passive holdings of financial assets (stocks and bonds) and is indeed recorded on the **capital account** of the BOP. FPI is generally considered **more volatile** or "hot money" than **Foreign Direct Investment (FDI)** because FPI can be quickly withdrawn in response to short-term economic changes or market sentiment, whereas FDI involves establishing lasting interests and physical assets, making it difficult to reverse quickly.

व्याख्या- कथन 1 गलत है। चालू खाता घाटा (CAD) का मतलब है कि किसी देश के वस्तुओं और सेवाओं के आयात के मूल्य का योग, **प्लस** विदेशों से उसकी शुद्ध आय (जैसे ब्याज और लाभांश), और **प्लस** शुद्ध चालू हस्तांतरण (जैसे प्रेषण) संबंधित निर्यात से **अधिक** है। कथन में एकतरफा हस्तांतरण और आय प्रवाह को गलत तरीके से *अपवर्जित* किया गया है। चालू खाता निम्नलिखित में विभाजित है: 1. व्यापार संतुलन (वस्तुएँ), 2. अदृश्य (सेवाएँ, आय और हस्तांतरण)। ये सभी घटक सामूहिक रूप से CAD का निर्धारण करते हैं। कथन 2 सही है। **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)** वित्तीय परिसंपत्तियों (स्टॉक और बॉन्ड) की निष्क्रिय होल्डिंग्स का प्रतिनिधित्व करता है और वास्तव में BOP के **पूंजी खाते** पर दर्ज किया जाता है। FPI को आम तौर पर **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)** की तुलना में **अधिक अस्थिर** या "गर्म धन" माना जाता है क्योंकि FPI को अल्पकालिक आर्थिक परिवर्तनों या बाजार की भावना के जवाब में जल्दी से वापस लिया जा सकता है, जबकि FDI में स्थायी हित और भौतिक संपत्ति स्थापित करना शामिल होता है, जिससे इसे जल्दी से पलटना मुश्किल हो जाता है।

25.

Answer- (d)

Explanation- All four components mentioned are key constituents of India's **Foreign Exchange Reserves**, which are managed by the Reserve Bank of India (RBI):

1. **Foreign Currency Assets (FCAs)**: These are assets held in foreign currencies (like USD, Euro, Yen) and are the largest component.
2. **Gold Reserves**: These are gold holdings.

VAID ICS:UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

3. **Special Drawing Rights (SDRs)**: These are international reserve assets created by the IMF and allocated to its members.

4. **Reserve Position in the IMF (RPIF)**: This is the portion of the quota that a member country must provide to the IMF in reserve assets and can be drawn upon by the country at short notice.

All four components are officially reported by the RBI as part of the total Forex Reserves.

व्याख्या- उल्लिखित सभी चार घटक भारत के **विदेशी विनिमय भंडार** के प्रमुख अंग हैं, जिनका प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है:

1. **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCAs)**: ये विदेशी मुद्राओं (जैसे USD, यूरो, येन) में रखी गई परिसंपत्तियाँ हैं और सबसे बड़ा घटक हैं।

2. **स्वर्ण भंडार**: ये स्वर्ण होल्डिंग्स हैं।

3. **विशेष आहरण अधिकार (SDRs)**: ये IMF द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्तियाँ हैं और इसके सदस्यों को आवंटित की जाती हैं।

4. **IMF में आरक्षित स्थिति (RPIF)**: यह कोटे का वह हिस्सा है जिसे एक सदस्य देश को IMF को आरक्षित परिसंपत्तियों में प्रदान करना होता है और देश द्वारा अल्प सूचना पर निकाला जा सकता है।

सभी चार घटकों को RBI द्वारा आधिकारिक तौर पर कुल विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

26.

Answer- (b)

Explanation- The contribution of the Agriculture and allied sectors (which includes forestry and fishing) to India's Gross Domestic Product (GDP) has been steadily declining over the years, a trend typical of economic development as the share of the industry and services sectors increases. However, it still remains a significant contributor. In recent years, based on constant prices, the contribution of the agriculture and allied sector to the total Gross Value Added (GVA)/GDP has hovered in the range of **15% to 18%.** For instance, it was approximately 18.8% in 2020-21 (during the pandemic) and around 18.3% in 2021-22, and has since stabilized towards the lower end of this range or slightly below. This figure must be contrasted with its much larger share in employment (around 45%), which highlights the issue of low productivity and disguised unemployment in the sector.

व्याख्या- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (जिसमें वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं) का योगदान वर्षों से लगातार घट रहा है, जो उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण आर्थिक विकास की एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। हालाँकि, यह अभी भी एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। हाल के वर्षों में, स्थिर मूल्यों के आधार पर, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA)/GDP में योगदान **15% से 18%** की सीमा में रहा है। उदाहरण के लिए, 2020-21 में (महामारी के दौरान) यह लगभग 18.8% और 2021-22 में लगभग 18.3% था, और तब से इस सीमा के निचले सिरे की ओर या थोड़ा नीचे स्थिर हो गया है। इस आँकड़े की तुलना रोजगार में इसकी कहीं बड़ी हिस्सेदारी (लगभग 45%) से की जानी चाहिए, जो इस क्षेत्र में कम उत्पादकता और प्रच्छन्न बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रकाश डालता है।

VAID IAS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

27.

Answer- (b)

Explanation- Statement I is correct. PMJDY accounts are eligible for an **overdraft facility up to ₹10,000** for eligible account holders (subject to conditions like satisfactory operation for a specific period). This facility aims to provide a basic credit mechanism to the poor, which is a key component of financial inclusion. **Statement II is correct.** The **RuPay Card** is India's own domestic card network, launched by **NPCI**, which facilitates transactions and is issued to PMJDY account holders. This is a crucial step towards digital payments and financial inclusion. However, **Statement II does not explain Statement I**. The RuPay Card (digital payments) and the Overdraft facility (credit access) are two **separate and distinct features** of the PMJDY scheme, both contributing to financial inclusion, but one is not the reason or explanation for the other. The overdraft facility is explained by the need for micro-credit, not by the existence of the RuPay card.

व्याख्या- कथन I सही है। PMJDY खाते पात्र खाताधारकों के लिए **₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा** के लिए पात्र हैं (एक विशिष्ट अवधि के लिए संतोषजनक संचालन जैसी शर्तों के अधीन)। इस सुविधा का उद्देश्य गरीबों को एक बुनियादी ऋण तंत्र प्रदान करना है, जो वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख घटक है। **कथन II सही है।** **RuPay कार्ड** भारत का अपना घरेलू कार्ड नेटवर्क है, जिसे **NPCI** द्वारा लॉन्च किया गया है, जो लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है और PMJDY खाताधारकों को जारी किया जाता है। यह डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, **कथन II, कथन I की व्याख्या नहीं करता है**। RuPay कार्ड (डिजिटल भुगतान) और ओवरड्राफ्ट सुविधा (ऋण पहुँच) PMJDY योजना की दो **अलग और विशिष्ट विशेषताएँ** हैं, दोनों वित्तीय समावेशन में योगदान करती हैं, लेकिन एक दूसरे का कारण या व्याख्या नहीं है। ओवरड्राफ्ट सुविधा को सूक्ष्म-ऋण की आवश्यकता से समझाया जाता है, न कि RuPay कार्ड के अस्तित्व से।

28.

Answer- (c)

Explanation- Statement 1 is correct. Public Sector Undertakings (PSUs) historically, and often currently, dominate the **core and strategic sectors** like defence, atomic energy, and railways in India, reflecting the government's strategic control over these essential areas. Statement 2 is incorrect. The core principle of **Public-Private Partnerships (PPPs)** is the **sharing of risks, responsibilities, and rewards** between the public and private sectors. It is not about transferring *all* risks to the private entity; rather, risks are generally allocated to the party best able to manage them (e.g., construction risk to the private sector, policy/legal risk to the public sector). Statement 3 is correct. **Disinvestment** is the action of a government selling or liquidating an asset or subsidiary. The Indian government's disinvestment policy aims to **promote efficiency** by introducing private-sector management practices and to **mobilize resources** (capital) from the sale of shares to fund its development and social sector programs. Therefore, only statements 1 and 3 are correct.

VAID ICS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

व्याख्या- कथन 1 सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) ऐतिहासिक रूप से, और अक्सर वर्तमान में, भारत में रक्षा, परमाणु ऊर्जा और रेलवे जैसे **मुख्य और रणनीतिक क्षेत्रों** पर हावी हैं, जो इन आवश्यक क्षेत्रों पर सरकार के रणनीतिक नियंत्रण को दर्शाते हैं। कथन 2 गलत है। **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs)** का मूल सिद्धांत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच **जोखिमों, जिम्मेदारियों और पुरस्कारों को साझा करना** है। यह *सभी* जोखिमों को निजी संस्था को हस्तांतरित करने के बारे में नहीं है; बल्कि, जोखिमों को आम तौर पर उस पक्ष को आवंटित किया जाता है जो उनका सबसे अच्छी तरह से प्रबंधन करने में सक्षम होता है (उदाहरण के लिए, निजी क्षेत्र को निर्माण जोखिम, सार्वजनिक क्षेत्र को नीति/कानूनी जोखिम)। कथन 3 सही है। **विनिवेश** किसी संपत्ति या सहायक कंपनी को बेचने या परिसमापन करने की सरकारी कार्रवाई है। भारत सरकार की विनिवेश नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र के प्रबंधन प्रथाओं को लागू करके **दक्षता को बढ़ावा देना** और अपने विकास और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को निधि देने के लिए शेयरों की बिक्री से **संसाधन (पूंजी) जुटाना** है। इसलिए, केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

29.

Answer- (d)

Explanation- Statements (a), (b), and (c) are correct. India's exchange rate regime is indeed a 'managed float', meaning the exchange rate is primarily market-determined, but the RBI intervenes to manage excessive volatility, not to fix a specific rate. Statement (d) is incorrect. While the RBI does use both spot and forward markets for intervention, the **primary purpose of foreign exchange market intervention is to manage the volatility of the exchange rate**, not explicitly to **offset a persistent current account deficit (CAD)**. A CAD is an outcome of fundamental economic factors (savings-investment gap) and trade imbalances; the RBI's role is to maintain orderly market conditions, not to directly nullify the effects of the CAD through market operations.

व्याख्या- कथन (a), (b) और (c) सही हैं। भारत की विनिमय दर व्यवस्था वास्तव में एक **'प्रबंधित लचीलापन'** है, जिसका अर्थ है कि विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन RBI **अत्यधिक अस्थिरता का प्रबंधन करने** के लिए हस्तक्षेप करता है, न कि किसी विशिष्ट दर को स्थिर करने के लिए।

कथन (d) गलत है। हालाँकि RBI हस्तक्षेप के लिए **हाजिर** और **वायदा** दोनों बाजारों का उपयोग करता है, विदेशी विनिमय बाजार हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य विनिमय दर की **अस्थिरता का प्रबंधन** करना है, न कि स्पष्ट रूप से लगातार **चालू खाता घाटे (CAD) को समायोजित** करना।

CAD मौलिक आर्थिक कारकों (बचत-निवेश अंतराल) और व्यापार असंतुलन का एक परिणाम है; RBI की भूमिका **व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखना** है, न कि बाजार संचालन के माध्यम से CAD के प्रभावों को सीधे **रद्द** करना।

30.

Answer- (d)

Explanation- Statement 1 is correct. The Public Distribution System (PDS) is the primary mechanism for implementing the provisions of the **National Food Security Act (NFSA), 2013**, providing subsidized food grains (rice, wheat, coarse grains) to about two-thirds of the country's population. Statement 2 is correct. The **Food Corporation of India (FCI)**, under the Department of Food and Public Distribution, is the central nodal agency entrusted with the key functions of procuring food grains from farmers at Minimum Support Price (MSP), ensuring their safe storage

VAID ICS:UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

(buffer stock), and making them available for distribution under the PDS and other welfare schemes. Statement 3 is correct. The twin objectives of maintaining the buffer stock are: **Food Security** (ensuring food availability throughout the year) and **Price Stability** (releasing surplus stock into the open market during inflationary periods or lean seasons to moderate prices). Since all three statements are correct, the correct option is (d).

व्याख्या- कथन 1 सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** के प्रावधानों को लागू करने का प्राथमिक तंत्र है, जो देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती खाद्यान्न (चावल, गेहूँ, मोटा अनाज) प्रदान करती है। कथन 2 सही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** वह केंद्रीय नोडल एजेंसी है जिसे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदने, उनके सुरक्षित भंडारण (बफर स्टॉक) को सुनिश्चित करने और उन्हें PDS तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए उपलब्ध कराने के प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं। कथन 3 सही है। बफर स्टॉक बनाए रखने के दोहरे उद्देश्य हैं: **खाद्य सुरक्षा** (पूरे वर्ष खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना) और **मूल्य स्थिरता** (मुद्रास्फीति की अवधि या कमजोर मौसमों के दौरान कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में अधिशेष स्टॉक जारी करना)। चूँकि तीनों कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प (d) है।

31.

Answer- (c)

Explanation- Statement (a), (c), and (d) are correct. NBFCs are indeed registered under the Companies Act and regulated by the RBI. They offer specialized lending (e.g., microfinance, infrastructure finance) and, unlike banks, they are not part of the payment system and cannot issue cheques. **Statement (b) is incorrect.** One of the fundamental differences between an NBFC and a bank is that **NBFCs cannot accept demand deposits** (deposits that can be withdrawn by the customer on demand, like current or savings accounts). They can only accept term deposits (fixed deposits) for a minimum period of 12 months, and even this is subject to RBI guidelines. Their inability to accept demand deposits and their exclusion from the payment system are the two main characteristics that distinguish them from commercial banks.

व्याख्या- कथन (a), (c), और (d) सही हैं। NBFCs वास्तव में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और RBI द्वारा विनियमित हैं। वे विशेष ऋण सेवाएँ प्रदान करती हैं (उदाहरण के लिए, सूक्ष्म वित्त, अवसंरचना वित्त) और, बैंकों के विपरीत, वे भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं और चेक जारी नहीं कर सकती हैं। **कथन (b) गलत है।** NBFC और बैंक के बीच मूलभूत अंतरों में से एक यह है कि **NBFCs माँग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं** (माँग पर ग्राहक द्वारा निकाले जा सकने वाले जमा, जैसे चालू या बचत खाते)। वे केवल न्यूनतम 12 महीने की अवधि के लिए सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) स्वीकार कर सकती हैं, और यह भी RBI के दिशानिर्देशों के अधीन है। माँग जमा स्वीकार करने में उनकी अक्षमता और भुगतान प्रणाली से उनका बहिष्कार वे दो मुख्य विशेषताएँ हैं जो उन्हें वाणिज्यिक बैंकों से अलग करती हैं।

32.

Answer- (a)

Explanation- Statement I is correct. The License Raj was a system of strict government controls, permits, and licenses required for setting up or expanding industrial units, which was a major factor inhibiting growth. The shift to LPG was a response to a severe economic crisis and the

VAID IAS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

recognition that these bureaucratic procedures needed to be removed to unleash the potential of the Indian economy. Statement II is correct. The **New Industrial Policy (NIP) of 1991** was the key policy measure of the liberalization era, and a cornerstone of this policy was the near-total abolition of the industrial licensing system, retaining it only for a small list of industries for security and environmental reasons. **Statement II explains Statement I**. The policy action described in Statement II (removing licensing) is the direct *mechanism* used to achieve the goal described in Statement I (dismantling bureaucratic procedures to boost growth). Hence, the causal link is strong.

व्याख्या- कथन I सही है। लाइसेंस राज औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए आवश्यक सख्त सरकारी नियंत्रणों, परमिटों और लाइसेंसों की एक प्रणाली थी, जो विकास को बाधित करने वाला एक प्रमुख कारक था। LPG में बदलाव एक गंभीर आर्थिक संकट और इस मान्यता की प्रतिक्रिया थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर करने के लिए इन नौकरशाही प्रक्रियाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। कथन II सही है। **1991 की नई औद्योगिक नीति (NIP)** उदारीकरण युग का प्रमुख नीतिगत उपाय था, और इस नीति का एक आधारशिला औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का लगभग कुल उन्मूलन था, इसे केवल सुरक्षा और पर्यावरणीय कारणों से उद्योगों की एक छोटी सूची के लिए बनाए रखा गया था। **कथन II, कथन I की व्याख्या करता है**। कथन II में वर्णित नीतिगत कार्रवाई (लाइसेंसिंग हटाना) कथन I में वर्णित लक्ष्य (विकास को बढ़ावा देने के लिए नौकरशाही प्रक्रियाओं को समाप्त करना) को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सीधा *तंत्र* है। इसलिए, कारण संबंध मजबूत है।

33.

Answer- (d)

Explanation- Statements (a), (b), and (c) are correct. MSP is announced before the season to guide farmers, recommended by the CACP, and acts as a floor price to prevent distress sales. **Statement (d) is incorrect.** As of now, the Minimum Support Price (MSP) mechanism in India is **not legally binding** on private traders or processors. MSP is an assurance from the government that designated public agencies (like FCI, NAFED) will procure the produce from farmers at the announced price if the market price falls below it. Private market transactions are generally governed by market forces, although there have been persistent demands and policy discussions about making MSP a legally guaranteed price for all buyers.

व्याख्या- कथन (a), (b), और (c) सही हैं। MSP किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए मौसम से पहले घोषित किया जाता है, CACP द्वारा अनुशंसित होता है, और संकटग्रस्त बिक्री को रोकने के लिए एक न्यूनतम मूल्य के रूप में कार्य करता है। **कथन (d) गलत है।** अभी तक, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र निजी व्यापारियों या प्रोसेसरों पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** है। MSP सरकार की ओर से एक आश्वासन है कि नामित सार्वजनिक एजेंसियाँ (जैसे FCI, NAFED) किसानों से घोषित मूल्य पर उपज खरीदेंगी यदि बाजार मूल्य इससे नीचे गिर जाता है। निजी बाजार लेनदेन आम तौर पर बाजार की ताकतों द्वारा शासित होते हैं, हालाँकि MSP को सभी खरीदारों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत मूल्य बनाने के बारे में लगातार मांगें और नीतिगत चर्चाएँ होती रही हैं।

VAID IAS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

34.

Answer- (c)

Explanation- Statement I is correct. Increasing the share of non-fossil fuel-based energy, especially solar, is essential for India's Paris Agreement commitments (Intended Nationally Determined Contributions - INDCs) and for reducing dependence on imported fossil fuels (energy security). Statement II is correct. The **National Solar Mission (NSM)**, launched in 2010, is indeed one of the key policy instruments to promote the large-scale deployment of solar technologies, thus directly supporting the goal in Statement I. Statement III is incorrect. The **Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY)** was launched to tackle the financial issues of **Power Distribution Companies (DISCOMs)**, not to provide financial subsidies to solar panel manufacturers. Schemes like the Production Linked Incentive (PLI) scheme for High-Efficiency Solar PV Modules or the National Green Hydrogen Mission are more relevant to promoting manufacturing and self-reliance in the solar sector. **Only Statement II is correct and explains Statement I**. NSM (Statement II) is the core *policy mechanism* for promoting solar energy (the goal in Statement I). Statement III is incorrect and therefore cannot explain Statement I.

व्याख्या- कथन I सही है। गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना, भारत की पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं (इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान - INDCs) को पूरा करने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने (ऊर्जा सुरक्षा) के लिए आवश्यक है। कथन II सही है। **राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM)**, जिसे 2010 में शुरू किया गया था, वास्तव में सौर प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीतिगत साधनों में से एक है, इस प्रकार यह सीधे कथन I के लक्ष्य का समर्थन करता है। कथन III गलत है। **उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY)** को **बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs)** के वित्तीय मुद्दों से निपटने के लिए शुरू किया गया था, न कि सौर पैनल निर्माताओं को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करने के लिए। उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना या राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाएँ सौर क्षेत्र में विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रासंगिक हैं। **केवल कथन II सही है और कथन I की व्याख्या करता है**। NSM (कथन II) सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य *नीति तंत्र* है (कथन I में लक्ष्य)। कथन III गलत है और इसलिए कथन I की व्याख्या नहीं कर सकता है।

35.

Answer- (d)

Explanation- The Current Account of the Balance of Payments records transactions relating to current income and expenditure. It has two main sub-heads: **Merchandise** (Trade in Goods) and **Invisibles**. The 'Invisibles' section further comprises:

1. **Services:** Exports and imports of services (e.g., Software, Shipping, Tourism).
2. **Income:** Investment income (e.g., interest, dividends, profit) received or paid.
3. **Transfers:** Current transfers/Unilateral transfers (e.g., Remittances, Gifts).

Evaluation of the statements:

1. **Software Services Exports:** Correctly categorized under **Services** (Invisibles).
2. **Remittances from NRIs:** Correctly categorized under **Transfers** (Invisibles).

VAID IAS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

3. **Foreign Direct Investment (FDI) inflows:** Incorrect. FDI is a long-term capital flow and is recorded in the **Capital Account**, not the Current Account.
4. **Interest received on loans extended to foreign countries:** Correctly categorized under **Income** (Invisibles). Therefore, statements 1, 2, and 4 are correct.

व्याख्या- भुगतान संतुलन का चालू खाता चालू आय और व्यय से संबंधित लेन-देन को रिकॉर्ड करता है। इसके दो मुख्य उप-शीर्ष हैं: **मर्चेंडाइज** (वस्तुओं में व्यापार) और **अदृश्य**। 'अदृश्य' खंड में आगे शामिल हैं:

1. **सेवाएँ**: सेवाओं का निर्यात और आयात (जैसे सॉफ्टवेयर, शिपिंग, पर्यटन)।
2. **आय**: प्राप्त या भुगतान की गई निवेश आय (जैसे ब्याज, लाभांश, लाभ)।
3. **हस्तांतरण**: चालू हस्तांतरण/एकतरफा हस्तांतरण (जैसे प्रेषण, उपहार)।

कथनों का मूल्यांकन:

1. **सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात**: **सेवाएँ** (अदृश्य) के तहत सही ढंग से वर्गीकृत।
2. **अनिवासी भारतीयों (NRIs) से प्रेषण**: **हस्तांतरण** (अदृश्य) के तहत सही ढंग से वर्गीकृत।
3. **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह**: गलत। FDI एक दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह है और चालू खाते में नहीं, बल्कि **पूंजी खाते** में दर्ज किया जाता है।
4. **विदेशी देशों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज**: **आय** (अदृश्य) के तहत सही ढंग से वर्गीकृत। इसलिए, कथन 1, 2 और 4 सही हैं।

36.

Answer- (a)

Explanation- Statement 1 is correct. If there is a strong capital inflow or a large current account surplus, the demand for the Rupee increases, which can lead to its excessive appreciation. To prevent this, the RBI can intervene in the spot market by **buying foreign currency (e.g., USD)** and simultaneously **selling the Rupee**. This action increases the supply of the Rupee and reduces the supply of the USD, thus moderating the Rupee's appreciation. Statement 2 is incorrect. India follows a **managed float exchange rate system**, not a fixed exchange rate system. The RBI's primary objective is to **manage volatility and maintain orderly conditions** in the foreign exchange market, not to maintain a *fixed* exchange rate band. It allows the exchange rate to be determined by market forces. Therefore, only statement 1 is correct.

व्याख्या- कथन 1 सही है। यदि मजबूत पूंजी प्रवाह या बड़ा चालू खाता अधिशेष होता है, तो रुपये की मांग बढ़ जाती है, जिससे इसका अत्यधिक अधिमूल्यन हो सकता है। इसे रोकने के लिए, RBI **विदेशी मुद्रा (जैसे USD) खरीदकर** और साथ ही **रुपये बेचकर** स्पॉट बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है। यह कार्रवाई रुपये की आपूर्ति को बढ़ाती है और USD की आपूर्ति को कम करती है, जिससे रुपये के अधिमूल्यन को नियंत्रित किया जाता है। कथन 2 गलत है। भारत **प्रबंधित लचीला (managed float) विनिमय दर प्रणाली** का पालन करता है, न कि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली का। विदेशी विनिमय बाजार हस्तक्षेप में RBI का प्राथमिक उद्देश्य एक *निश्चित* विनिमय दर बैंड बनाए रखना नहीं, बल्कि अस्थिरता का प्रबंधन करना और बाजार में व्यवस्थित स्थिति बनाए रखना है। यह विनिमय दर को बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित होने की अनुमति देता है। इसलिए, केवल कथन 1 सही है।

VAID ICS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

37.

Answer- (d)

Explanation- The situation described is known as **Disguised Unemployment** (or hidden unemployment). It occurs when more people are employed in a sector, such as agriculture, than are actually required. If some of these workers were removed, the total output would remain unchanged, meaning their **marginal productivity of labour is zero**. This is a chronic issue in the Indian agricultural sector due to fragmented landholdings and lack of non-farm employment opportunities in rural areas, leading to poverty and low per capita income among farm households. Seasonal unemployment (option a) is also prevalent in agriculture but is defined by the lack of work during specific times of the year (e.g., non-sowing/non-harvesting periods).

व्याख्या- वर्णित स्थिति को **प्रच्छन्न बेरोजगारी** (या छिपी हुई बेरोजगारी) के रूप में जाना जाता है। यह तब होती है जब कृषि जैसे क्षेत्र में वास्तव में आवश्यक लोगों की तुलना में अधिक लोग कार्यरत होते हैं। यदि इनमें से कुछ श्रमिकों को हटा दिया जाए, तो कुल उत्पादन अपरिवर्तित रहेगा, जिसका अर्थ है कि उनके **श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है**। यह खंडित भूमि जोत और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र में एक पुरानी समस्या है, जिससे किसान परिवारों के बीच गरीबी और कम प्रति व्यक्ति आय होती है। मौसमी बेरोजगारी (विकल्प a) भी कृषि में प्रचलित है, लेकिन इसे वर्ष के विशिष्ट समय (उदाहरण के लिए, गैर-बुवाई/गैर-कटाई की अवधि) के दौरान काम की कमी से परिभाषित किया जाता है।

38.

Answer- (b)

Explanation- Statement 1 is incorrect. While the 1991 reforms significantly reduced the role of PSUs, they did not lead to the **total elimination** of PSUs in non-strategic sectors. Disinvestment was a gradual process, and many PSUs continue to operate, though often facing competition. The shift was one of liberalization and disinvestment, not total elimination. Statement 2 is correct. The current government policy on Public Sector Enterprises (PSEs) involves the classification of sectors as **strategic and non-strategic**. The goal is to retain a minimum, bare presence of PSEs in **strategic sectors** (like Atomic Energy, Space, Defence) and to privatize or implement disinvestment in **non-strategic sectors** (like Hospitality, certain manufacturing units). This approach aims to minimize the government's presence in non-essential domains. Therefore, only statement 2 is correct.

व्याख्या- कथन 1 गलत है। हालाँकि 1991 के सुधारों ने PSUs की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से कम कर दिया, लेकिन उन्होंने गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में PSUs के **पूर्ण उन्मूलन** को जन्म नहीं दिया। विनिवेश एक क्रमिक प्रक्रिया थी, और कई PSUs प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए भी काम करना जारी रखते हैं। यह बदलाव उदारीकरण और विनिवेश का था, न कि पूर्ण उन्मूलन का। कथन 2 सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) पर वर्तमान सरकारी नीति में क्षेत्रों को **रणनीतिक और गैर-रणनीतिक** के रूप में वर्गीकृत करना शामिल है। लक्ष्य **रणनीतिक क्षेत्रों** (जैसे परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा) में PSEs की न्यूनतम, नगण्य उपस्थिति बनाए रखना और **गैर-रणनीतिक क्षेत्रों** (जैसे आतिथ्य, कुछ विनिर्माण इकाइयाँ) में निजीकरण या विनिवेश को लागू करना है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य गैर-आवश्यक डोमेन में सरकार की उपस्थिति को कम करना है। इसलिए, केवल कथन 2 सही है।

VAID ICS-UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

39.

Answer- (d)

Explanation- All four listed initiatives are key components or instruments aimed at promoting **financial inclusion** in India: 1. **PMJDY:** Provides universal access to banking services, including a basic savings account, for the unbanked. 2. **RuPay Card:** An indigenous domestic card network providing affordable debit card services, enhancing access to digital payments, which is a component of inclusion. 3. **UPI:** A real-time payment system that has revolutionized digital transactions, making payments accessible to all via mobile phones, greatly furthering inclusion. 4. **Stand Up India Scheme:** Provides bank loans between ₹10 lakh and ₹1 crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch. By ensuring access to **institutional credit** for marginalized sections, it is a crucial financial inclusion initiative. Therefore, all four are correct.

व्याख्या- सूचीबद्ध सभी चार पहलें भारत में **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख घटक या साधन माने जाते हैं: 1. **PMJDY:** अनबैंक्ड (जिनके पास बैंक खाता नहीं है) के लिए एक बुनियादी बचत खाता सहित बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करता है। 2. **RuPay कार्ड:** एक स्वदेशी घरेलू कार्ड नेटवर्क जो सस्ती डेबिट कार्ड सेवाएँ प्रदान करता है, डिजिटल भुगतान तक पहुँच को बढ़ाता है, जो समावेशन का एक घटक है। 3. **UPI:** एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली जिसने डिजिटल लेनदेन में क्रांति ला दी है, मोबाइल फोन के माध्यम से सभी के लिए भुगतान को सुलभ बनाया है, जिससे समावेशन को बहुत आगे बढ़ाया गया है। 4. **स्टैंड अप इंडिया योजना:** प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ₹10 लाख और ₹1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करता है। हाशिए के वर्गों के लिए **संस्थागत ऋण** तक पहुँच सुनिश्चित करके, यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन पहल है। इसलिए, सभी चार सही हैं।

40.

Answer- (a)

Explanation- Statement 1 is correct. The **WTO** is the global international organization dealing with the rules of trade between nations. Its key functions include administering trade agreements, acting as a forum for trade negotiations, and handling **dispute settlement**. Statement 2 is correct. WTO rulings from the Dispute Settlement Body are indeed **legally binding** on members. However, the WTO has no enforcement power like a police force or a judicial system. Enforcement relies on **retaliatory trade measures (sanctions)** authorized by the WTO, which is the main way to induce compliance. Statement 3 is incorrect. The WTO's **Agreement on Agriculture (AoA)** does not require India to eliminate *all* agricultural subsidies. India is a developing country and is allowed to provide certain subsidies (e.g., input subsidies, certain domestic support measures, and minimum support prices below a de minimis level of 10% of the value of production) categorized under the **Green Box and Blue Box** measures, and also has special provisions for Public Stockholding for food security. Therefore, only statements 1 and 2 are correct.

VAIDICS:UPSC (CSE) PRE 2026 MOCK TEST SERIES

व्याख्या- कथन 1 सही है। **WTO** राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके प्रमुख कार्यों में व्यापार समझौतों का प्रशासन करना, व्यापार वार्ता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना और **विवाद निपटान** को संभालना शामिल है। कथन 2 सही है। विवाद निपटान निकाय से WTO के निर्णय वास्तव में सदस्यों पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी** होते हैं। हालाँकि, WTO के पास पुलिस बल या न्यायिक प्रणाली जैसी कोई प्रवर्तन शक्ति नहीं है। प्रवर्तन **प्रतिशोधात्मक व्यापार उपायों (प्रतिबंधों)** पर निर्भर करता है जो WTO द्वारा अधिकृत होते हैं, जो अनुपालन प्रेरित करने का मुख्य तरीका है। कथन 3 गलत है। WTO के **कृषि समझौते (AoA)** के लिए भारत को *सभी* कृषि सब्सिडी समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भारत एक विकासशील देश है और उसे कुछ सब्सिडी (उदाहरण के लिए, इनपुट सब्सिडी, कुछ घरेलू समर्थन उपाय, और उत्पादन मूल्य के 10% के डी मिनिमिस स्तर से नीचे न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रदान करने की अनुमति है, जिन्हें **ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स** उपायों के तहत वर्गीकृत किया गया है, और खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए विशेष प्रावधान भी हैं। इसलिए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

41.

Answer- (a)

Explanation- Statement (a) is incorrect. The New Industrial Policy of 1991 **did not completely abolish** industrial licensing for *all* sectors. It retained licensing for a small list of strategic, environmental, and public safety sectors, such as defense products, industrial explosives, and a few hazardous chemicals, though the list has been pruned over time. Statements (b), (c), and (d) are correct descriptions of the post-1991 economic reforms and the objectives of the 'Make in India' initiative and the EoDB framework. The opening up of previously reserved sectors (d) was a key component of the liberalization.

व्याख्या- कथन (a) गलत है। 1991 की नई औद्योगिक नीति ने *सभी* क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को **पूरी तरह से समाप्त नहीं किया**। इसने रक्षा उत्पादों, औद्योगिक विस्फोटकों और कुछ खतरनाक रसायनों जैसे रणनीतिक, पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों की एक छोटी सूची के लिए लाइसेंसिंग को बरकरार रखा, हालाँकि इस सूची को समय के साथ छाँटा गया है। कथन (b), (c) और (d) 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों और 'मेक इन इंडिया' पहल तथा EoDB ढाँचे के उद्देश्यों का सही वर्णन हैं। पहले आरक्षित क्षेत्रों (d) को खोलना उदारीकरण का एक प्रमुख घटक था।

42.

Answer- (c)

Explanation- Statement (a), (b), and (d) are correct definitions and facts related to NPAs and the reform process. **Statement (c) is incorrect.** The **Asset Quality Review (AQR)** was a **regulatory exercise** by the RBI aimed at forcing banks to **recognize** and **disclose** the true extent of their NPAs and make adequate provisions, thereby cleaning up the balance sheets. The AQR **did not** provide direct funds for bank recapitalization. Recapitalization (the provision of funds) was a subsequent action taken by the Government of India (e.g., under the Indradhanush plan) to restore the capital of PSBs after the AQR exposed the massive shortfall created by the provisioning for NPAs.

व्याख्या- कथन (a), (b) और (d) NPAs और सुधार प्रक्रिया से संबंधित सही परिभाषाएँ और तथ्य हैं। **कथन (c) गलत है। परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR)** RBI द्वारा एक **नियामक अभ्यास** था जिसका उद्देश्य बैंकों को उनके NPAs की वास्तविक

VAID IGS:UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

सीमा को **पहचानने** और **खुलासा** करने तथा पर्याप्त प्रावधान करने के लिए मजबूर करना था, जिससे बैलेंस शीट साफ हो सके। AQR ने बैंक पुनर्पूंजीकरण के लिए सीधे धन **प्रदान नहीं किया**। पुनर्पूंजीकरण (धन का प्रावधान) भारत सरकार द्वारा AQR द्वारा NPAs के प्रावधान के कारण उत्पन्न भारी कमी को उजागर करने के बाद PSBs की पूंजी को बहाल करने के लिए की गई एक बाद की कार्रवाई थी (उदाहरण के लिए, इंद्रधनुष योजना के तहत)।

43.

Answer- (d)

Explanation- Statement 1 is correct. **PM Gati Shakti** is indeed a **digital platform** that brings together 16 Ministries (like Railways, Roadways, Ports, Telecom) for integrated planning and synchronized project implementation. Statement 2 is incorrect. The plan focuses on **multi-modal connectivity**, encompassing roads, railways, ports, **waterways, and airports** (at least five modes), to reduce fragmentation and optimize logistics. The use of "only three modes" is incorrect. Statement 3 is correct. A primary objective is to significantly reduce high logistics costs in India by enabling seamless connectivity and efficient movement of goods and people. Statement 4 is correct. The platform utilizes advanced geospatial technology, including **satellite imagery** and **3D modeling**, to provide a single, comprehensive view of the entire national infrastructure landscape for better decision-making. Therefore, statements 1, 3, and 4 are correct.

व्याख्या- कथन 1 सही है। **PM गति शक्ति** वास्तव में एक **डिजिटल मंच** है जो एकीकृत नियोजन और समकालिक परियोजना कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों (जैसे रेलवे, सड़क मार्ग, बंदरगाह, दूरसंचार) को एक साथ लाता है। कथन 2 गलत है। यह योजना **बहु-मॉडल कनेक्टिविटी** पर केंद्रित है, जिसमें सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, **जलमार्गों और हवाई अड्डों** (कम से कम पाँच मोड) को शामिल किया गया है, ताकि विखंडन को कम किया जा सके और लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित किया जा सके। "केवल तीन मोड" का उपयोग गलत है। कथन 3 सही है। एक प्राथमिक उद्देश्य सहज कनेक्टिविटी और वस्तुओं तथा लोगों की कुशल आवाजाही को सक्षम करके भारत में उच्च लॉजिस्टिक्स लागत को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है। कथन 4 सही है। यह मंच बेहतर निर्णय लेने के लिए संपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना परिदृश्य का एक एकल, व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए **उपग्रह इमेजरी** और **3D मॉडलिंग** सहित उन्नत भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करता है। इसलिए, कथन 1, 3 और 4 सही हैं।

44.

Answer- (b)

Explanation- The **International Monetary Fund (IMF)** was established to foster **global monetary cooperation**, secure **financial stability**, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. Its core function is to provide financial assistance (loans) to countries facing balance of payments problems and to monitor the global financial system. Option (a) describes the function of the World Bank/International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Option (c) describes the function of the World Trade Organization (WTO).

व्याख्या- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना **वैश्विक मौद्रिक सहयोग** को बढ़ावा देने, **वित्तीय स्थिरता** को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए की गई थी। इसका मुख्य कार्य भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता

VAID IAS-UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

(ऋण) प्रदान करना और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करना है। विकल्प (a) विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) के कार्य का वर्णन करता है। विकल्प (c) विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कार्य का वर्णन करता है।

45.

Answer- (a)

Explanation- Statement I is correct. A **mixed economy** combines features of both capitalism (private sector and price mechanism) and socialism (public sector, planning, and state intervention). India's economy is defined by this dual guidance. Statement II is correct. The presence of the government (state) in critical sectors like defense, health, and education, often through PSUs or subsidized social programs, is the practical demonstration of the **social welfare component** of a mixed economy, which guides the market mechanism (Statement I) towards non-profit goals in these areas. Thus, the specific examples of state intervention in Statement II illustrate and provide the rationale for the generalized characteristic of India's mixed economy described in Statement I. Therefore, Statement II correctly explains Statement I.

व्याख्या- कथन I सही है। एक **मिश्रित अर्थव्यवस्था** पूंजीवाद (निजी क्षेत्र और मूल्य तंत्र) और समाजवाद (सार्वजनिक क्षेत्र, नियोजन और राज्य हस्तक्षेप) दोनों की विशेषताओं को जोड़ती है। भारत की अर्थव्यवस्था इस दोहरी मार्गदर्शन द्वारा परिभाषित है। कथन II सही है। रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार (राज्य) की उपस्थिति, अक्सर PSUs या रियायती सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के **सामाजिक कल्याण घटक** का व्यावहारिक प्रदर्शन है, जो इन क्षेत्रों में गैर-लाभकारी लक्ष्यों की ओर बाजार तंत्र (कथन I) का मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार, कथन II में राज्य हस्तक्षेप के विशिष्ट उदाहरण कथन I में वर्णित भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता को दर्शाते हैं और उसका तर्क प्रदान करते हैं। इसलिए, कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।

46.

Answer- (c)

Explanation- Statement 1 is correct. **FDI** represents investment with a lasting interest, categorized as a **long-term capital inflow** in the **Capital Account** of the BOP. Statement 2 is correct. The majority of sectors in India, including most of the manufacturing sector, permit **100% FDI under the Automatic Route** (no prior government approval required). Statement 3 is correct. As a major push towards the 'Make in India' initiative, **100% FDI is permitted under the Automatic Route in all manufacturing sectors**, subject to applicable laws and regulations. Statement 4 is incorrect. FDI is considered a **long-term** flow, contributing to the establishment of productive assets and technology transfer. While it does bring foreign currency, its primary impact is on structural growth and long-term capital, not short-term liquidity, which is more characteristic of FPI. Statement 5 is correct. FDI is generally considered **more stable** than FPI because it involves physical assets and managerial control, making its withdrawal difficult and slow, unlike FPI, which can be quickly pulled out. Therefore, four facts (1, 2, 3, and 5) are correct.

VAID IAS-UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

व्याख्या- कथन 1 सही है। **FDI** एक स्थायी हित के साथ निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे BOP के **पूंजी खाते** में **दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कथन 2 सही है। भारत में अधिकांश क्षेत्रों, जिनमें विनिर्माण क्षेत्र का अधिकांश भाग शामिल है, **स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI** की अनुमति देते हैं (किसी पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है)। कथन 3 सही है। 'मेक इन इंडिया' पहल की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, लागू कानूनों और विनियमों के अधीन, **सभी विनिर्माण क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है**। कथन 4 गलत है। FDI को एक **दीर्घकालिक** प्रवाह माना जाता है, जो उत्पादक परिसंपत्तियों की स्थापना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में योगदान देता है। हालाँकि यह विदेशी मुद्रा लाता है, इसका प्राथमिक प्रभाव अल्पकालिक तरलता पर नहीं, बल्कि संरचनात्मक विकास और दीर्घकालिक पूंजी पर होता है, जो FPI की अधिक विशेषता है। कथन 5 सही है। FDI को आमतौर पर FPI की तुलना में **अधिक स्थिर** माना जाता है क्योंकि इसमें भौतिक संपत्ति और प्रबंधकीय नियंत्रण शामिल होता है, जिससे इसकी निकासी मुश्किल और धीमी हो जाती है, FPI के विपरीत, जिसे जल्दी से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए, चार तथ्य (1, 2, 3 और 5) सही हैं।

47-

Answer- (b)

Explanation- Treasury Bills (**T-Bills**) are **short-term** money market instruments used by the **Government of India (GoI)** to meet its temporary funding needs. They are crucial because they typically mature in less than one year—specifically, they are issued in India for maturities of **91 days**, **182 days**, or **364 days**. This makes statement 2 correct, but statement 1 (long-term) incorrect. T-Bills are issued solely by the **Reserve Bank of India (RBI)** on behalf of the GoI. The issuance happens through a **competitive bidding process**, not through commercial banks, making statement 3 incorrect. They are zero-coupon instruments, meaning they are issued at a **discount** to their face value and redeemed at **par**.

व्याख्या- ट्रेजरी बिल (**टी-बिल**) भारत सरकार (GoI) द्वारा अपनी अस्थायी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले **अल्पकालिक** मुद्रा बाज़ार उपकरण हैं। वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आम तौर पर एक वर्ष से कम समय में परिपक्व होते हैं—विशेष रूप से, उन्हें भारत में **91 दिन**, **182 दिन**, या **364 दिन** की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। इससे कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 (दीर्घकालिक) गलत है।

टी-बिल केवल GoI की ओर से **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** द्वारा जारी किए जाते हैं। इन्हें **प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया** के माध्यम से जारी किया जाता है, न कि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से, जिससे कथन 3 गलत हो जाता है। वे जीरो-कूपन उपकरण हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने अंकित मूल्य पर **छूट** पर जारी किए जाते हैं और **समान मूल्य** पर भुनाए जाते हैं।

48-

Answer- (d)

Explanation- The incorrect statement is (d). The traditional definition of a Public Sector Enterprise (PSE) often required the government to hold at least a **51% equity stake** to maintain majority ownership. However, the current government policy, particularly under the new strategic and non-strategic sector classification, no longer mandates the retention of 51% stake in all PSEs. The policy's focus is on **privatization and strategic disinvestment**, which involves reducing the government's stake to below 51% and even transferring management control to private players (strategic sale), especially in non-strategic sectors. For strategic sectors, the goal

VAID IAS:UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

is to keep only a "bare minimum" presence, but even this does not strictly mean a 51% minimum in *every* PSE. Statements (a), (b), and (c) accurately reflect the current official policy of **minimum government presence** in strategic sectors and eventual privatization/disinvestment in non-strategic sectors to improve efficiency and resource allocation. The shift away from the 51% mandatory stake in all PSUs is a key indicator of the post-1991 liberalization and reform agenda.

व्याख्या- गलत कथन (d) है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) की पारंपरिक परिभाषा में अक्सर सरकार को बहुमत स्वामित्व बनाए रखने के लिए कम से कम **51% इक्विटी हिस्सेदारी** रखने की आवश्यकता होती थी। हालाँकि, वर्तमान सरकारी नीति, विशेष रूप से नए रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्र वर्गीकरण के तहत, अब सभी PSEs में 51% हिस्सेदारी बनाए रखने को अनिवार्य नहीं करती है। नीति का फोकस **निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश** पर है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी को 51% से नीचे कम करना और यहां तक कि निजी खिलाड़ियों को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित करना (रणनीतिक बिक्री), खासकर गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल है। रणनीतिक क्षेत्रों के लिए, लक्ष्य केवल एक "न्यूनतम" उपस्थिति रखना है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि *प्रत्येक* PSE में अनिवार्य रूप से 51% न्यूनतम हिस्सेदारी हो। कथन (a), (b), और (c) रणनीतिक क्षेत्रों में **न्यूनतम सरकारी उपस्थिति** और दक्षता तथा संसाधन आवंटन में सुधार के लिए गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में अंतिम निजीकरण/विनिवेश की वर्तमान आधिकारिक नीति को सही ढंग से दर्शाते हैं। सभी PSUs में 51% अनिवार्य हिस्सेदारी से दूर हटना 1991 के बाद के उदारीकरण और सुधार एजेंडे का एक प्रमुख संकेतक है।

49-

Answer- (c)

Explanation- The correct answer is (c). In the context of financial services and technology, **'last mile connectivity'** refers to the final segment of the delivery network that connects the primary service providers (like banks and government schemes) to the **end-users**, especially those in hard-to-reach, underserved, or rural locations. For **financial inclusion**, this goal means extending basic financial services such as bank accounts, savings, credit, insurance, and pensions to the **remotest rural areas and marginalized populations** who were previously excluded from the formal financial system. Initiatives like PM Jan Dhan Yojana, Business Correspondents (BCs), and the JAM (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) trinity are designed specifically to overcome this last-mile barrier by making transactions simpler, accessible, and affordable for the poor. Options (a), (b), and (d) describe aspects of financial technology and market integration, but they do not capture the core concept of reaching the most excluded individuals, which is central to the last-mile challenge of financial inclusion.

व्याख्या- सही उत्तर (c) है। वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, **'लास्ट माइल कनेक्टिविटी'** वितरण नेटवर्क के अंतिम खंड को संदर्भित करता है जो प्राथमिक सेवा प्रदाताओं (जैसे बैंक और सरकारी योजनाएँ) को **अंतिम-उपयोगकर्ताओं** से जोड़ता है, खासकर उन लोगों से जो दुर्गम, कम सेवा वाले या ग्रामीण स्थानों में हैं। **वित्तीय समावेशन** के लिए, इस लक्ष्य का अर्थ है कि बुनियादी वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा और पेंशन को **सबसे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए पर रहने वाली आबादी** तक विस्तारित करना जो पहले औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर थे। PM जन धन योजना, व्यवसाय संवाददाता (BCs), और JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) त्रयी जैसी पहलें विशेष रूप से लेनदेन को सरल, सुलभ और गरीबों के लिए किफायती बनाकर इस लास्ट माइल बाधा को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। विकल्प (a), (b), और (d) वित्तीय प्रौद्योगिकी

VAIDICS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

और बाजार एकीकरण के पहलुओं का वर्णन करते हैं, लेकिन वे सबसे बहिष्कृत व्यक्तियों तक पहुँचने की मूल अवधारणा को नहीं पकड़ते हैं, जो वित्तीय समावेशन की लास्ट माइल चुनौती के लिए केंद्रीय है।

50-

Answer- (c)

Explanation- The incorrect statement is (c). **Crop productivity in India is highly non-uniform across different states.** Productivity levels are significantly influenced by a variety of non-uniform factors, including climatic variations, soil quality differences, varying levels of access to irrigation (only about half of the net cropped area is irrigated), and highly uneven adoption rates of modern high-yield seed varieties, fertilizers, and farm mechanization. For instance, states in the North-West (like Punjab and Haryana) generally have much higher per-hectare yields for major crops than many states in the East or South. Therefore, claiming highly uniform productivity is factually incorrect. Statements (a), (b), and (d) accurately describe the major challenges facing the Indian rural economy: the need for non-farm employment (a), the problem of indebtedness (b), and the issue of post-harvest losses due to poor infrastructure (d).

व्याख्या- गलत कथन (c) है। **भारत में फसल उत्पादकता विभिन्न राज्यों में अत्यधिक असमान है।** उत्पादकता के स्तर विभिन्न असमान कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, जिनमें जलवायु भिन्नताएं, मिट्टी की गुणवत्ता में अंतर, सिंचाई तक पहुँच के विभिन्न स्तर (शुद्ध फसली क्षेत्र का केवल लगभग आधा सिंचित है), और आधुनिक उच्च उपज वाले बीज किस्मों, उर्वरकों और कृषि मशीनीकरण की अत्यधिक असमान अपनाने की दरें शामिल हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर-पश्चिम के राज्यों (जैसे पंजाब और हरियाणा) में प्रमुख फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर उपज आमतौर पर पूर्व या दक्षिण के कई राज्यों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसलिए, अत्यधिक समान उत्पादकता का दावा करना तथ्यात्मक रूप से गलत है। कथन (a), (b), और (d) भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का सही ढंग से वर्णन करते हैं: गैर-कृषि रोजगार की आवश्यकता (a), ऋणग्रस्तता की समस्या (b), और खराब अवसंरचना के कारण फसल कटाई के बाद के नुकसान का मुद्दा (d)।

51-

Answer- (c)

Explanation- The correct answer is (c). **'Stranded assets'** is a concept highly relevant to the global transition towards a low-carbon economy. It refers to assets, particularly in the **fossil fuel sector** (coal mines, oil and gas reserves, conventional power plants), that become economically **unviable or redundant** well before the end of their anticipated useful life. This premature devaluation is typically caused by external, unanticipated factors like stricter **climate change policies, technological shifts** (e.g., cheaper renewable energy), or sustained changes in market preferences (demand shift). In India, this risk is mainly associated with coal-based power generation and reserves as the country commits to large-scale renewable energy deployment and net-zero targets. The other options describe operational challenges or underutilized capacity, but 'stranded assets' specifically implies a permanent, systemic devaluation due to the transition away from the asset's underlying resource base.

VAID IAS-UPSC (CSE) PRE 2026 MOCK TEST SERIES

व्याख्या- सही उत्तर (c) है। **'फँसे हुए परिसंपत्तियाँ'** एक कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन से संबंधित एक अवधारणा है। यह उन परिसंपत्तियों को संदर्भित करता है, विशेष रूप से **जीवाश्म ईंधन क्षेत्र** (कोयला खदानें, तेल और गैस भंडार, पारंपरिक बिजली संयंत्र) में, जो उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के अंत से पहले ही आर्थिक रूप से **अव्यवहार्य या अनावश्यक** हो जाते हैं। यह समय से पहले अवमूल्यन आमतौर पर बाहरी, अप्रत्याशित कारकों जैसे सख्त **जलवायु परिवर्तन नीतियां, तकनीकी बदलाव** (जैसे, सस्ती अक्षय ऊर्जा), या बाजार वरीयताओं में निरंतर परिवर्तन (मांग में बदलाव) के कारण होता है। भारत में, यह जोखिम मुख्य रूप से कोयला-आधारित बिजली उत्पादन और भंडार से जुड़ा हुआ है क्योंकि देश बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परिनियोजन और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य विकल्प परिचालन चुनौतियों या कम उपयोग की गई क्षमता का वर्णन करते हैं, लेकिन 'फँसे हुए परिसंपत्तियाँ' विशेष रूप से संपत्ति के अंतर्निहित संसाधन आधार से दूर संक्रमण के कारण एक स्थायी, प्रणालीगत अवमूल्यन का तात्पर्य है।

52-

Answer- (a)

Explanation Statement 1 is correct. The National Multidimensional Poverty Index (MPI) by NITI Aayog, which is based on the global methodology of Alkire and Foster (AF), measures simultaneous deprivations across the three equally weighted dimensions of **Health, Education, and Standard of Living**. These three dimensions are further broken down into 12 indicators aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs). The indicators include Nutrition, Child and Adolescent Mortality, Maternal Health, Years of Schooling, School Attendance, Cooking Fuel, Sanitation, Drinking Water, Electricity, Housing, Assets, and Bank Accounts.

Statement 2 is incorrect. The Tendulkar Committee (2009) did recommend a **shift away from the calorie-based model** and broadened the poverty line to include private expenditure on **health and education**, along with clothing, footwear, and transport. However, it did **not** entirely remove consumption expenditure. Instead, it recommended moving to a poverty line based on a new reference consumption basket derived from the **Mixed Reference Period (MRP)** data, which included the nutritional requirements and the private expenditure on health and education. The committee's poverty line was still fundamentally based on a consumption basket, unlike the MPI which is a non-monetary measure of deprivation.

व्याख्या- कथन 1 सही है। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI), जो अल्केयर और फोस्टर (AF) की वैश्विक पद्धति पर आधारित है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के **तीन समान रूप से भारित आयामों** में एक साथ अभावों को मापता है। इन तीन आयामों को आगे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप 12 संकेतकों में विभाजित किया गया है। संकेतकों में पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं।

कथन 2 गलत है। तेंदुलकर समिति (2009) ने **कैलोरी-आधारित मॉडल से दूर** जाने की सिफारिश की थी और गरीबी रेखा को कपड़ों, जूते, परिवहन के साथ-साथ **स्वास्थ्य और शिक्षा** पर निजी व्यय को शामिल करने के लिए व्यापक बनाया था। हालाँकि, इसने उपभोग व्यय को **पूरी तरह से नहीं हटाया**। इसके बजाय, इसने **मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP)** के डेटा से प्राप्त एक नई संदर्भ उपभोग टोकरी पर आधारित गरीबी रेखा पर जाने की सिफारिश की, जिसमें पोषण संबंधी आवश्यकताएं और स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय शामिल था। समिति की गरीबी रेखा अभी भी मौलिक रूप से एक उपभोग टोकरी पर आधारित थी, जो MPI के विपरीत है, MPI अभाव का एक गैर-मौद्रिक माप है।

VAID IAS UPSC (OSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

53-

Answer- (b)

Explanation- Option (b) is correct. The directions state that a single regulated entity's investment in an AIF scheme cannot exceed 10% of that scheme's corpus.

Option (a) is incorrect as the new directions explicitly impose an individual cap of 10% and a collective cap of 20% for all REs combined.

Option (c) is incorrect. The revised directions still have provisioning norms, particularly for exposures greater than 5%, even though they are structured differently.

Option (d) is incorrect The new rules add provisioning requirements related to investments in subordinated units and do not simplify this process.

व्याख्या- विकल्प (b) सही है। निर्देशों में कहा गया है कि किसी AIF योजना में एक विनियमित संस्था का निवेश उस योजना की कुल राशि के 10% से अधिक नहीं हो सकता।

विकल्प (a) गलत है क्योंकि नए निर्देशों में स्पष्ट रूप से सभी RE के लिए 10% की व्यक्तिगत सीमा और 20% की सामूहिक सीमा निर्धारित की गई है।

विकल्प (c) गलत है। संशोधित निर्देशों में अभी भी प्रावधान मानदंड हैं, विशेष रूप से 5% से अधिक निवेश के लिए, भले ही उनकी संरचना अलग हो।

विकल्प (d) गलत है। नए नियम अधीनस्थ इकाइयों में निवेश से संबंधित प्रावधान आवश्यकताओं को जोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को सरल नहीं बनाते हैं।

54-

Answer- (d)

Explanation- Statement 1 is correct. The demographic dividend is the economic growth potential that can result from shifts in a population's age structure, mainly when the share of the working-age population (15-64 years) is larger than the non-working-age share (children and elderly). This typically happens following a decline in the Total Fertility Rate (TFR), which reduces the number of young dependents, thus lowering the overall dependency ratio.

Statement 2 is correct. While India has a large working-age population (the youth bulge), a key challenge is the quality of its human capital. A significant portion of the youth lack the industry-relevant skills and vocational training required for modern sectors, leading to a major **skill mismatch** and high unemployability, which is a critical policy challenge to realizing the demographic dividend.

Statement 3 is correct. As India urbanizes and the working-age population moves in search of employment, migration pressures on urban infrastructure and services will intensify. Furthermore, while India is currently young, the demographic transition is nearing its end. Projections indicate that the elderly population (60+ years) will increase substantially post-2050, necessitating policy planning for an aging society, social security, and health care for the elderly.

VAID IAS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

व्याख्या- कथन 1 सही है। जनसांख्यिकीय लाभांश वह आर्थिक विकास क्षमता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव से उत्पन्न हो सकती है, मुख्यतः जब कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या (15-64 वर्ष) का हिस्सा गैर-कामकाजी आयु वर्ग (बच्चे और बुजुर्ग) के हिस्से से बड़ा होता है। यह आमतौर पर कुल प्रजनन दर (TFR) में गिरावट के बाद होता है, जो युवा आश्रितों की संख्या को कम करता है, जिससे समग्र निर्भरता अनुपात कम हो जाता है।

कथन 2 सही है। हालाँकि भारत में कामकाजी आयु वर्ग की एक बड़ी आबादी (युवा उभार) है, इसकी मानव पूंजी की गुणवत्ता एक प्रमुख चुनौती है। युवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आधुनिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक उद्योग-प्रासंगिक कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण से वंचित है, जिससे एक बड़ा **कौशल बेमेल** और उच्च बेरोज़गारी उत्पन्न होती है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती है।

कथन 3 सही है। जैसे-जैसे भारत का शहरीकरण हो रहा है और कामकाजी आयु वर्ग के लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर प्रवासन का दबाव तेज होगा। इसके अलावा, हालाँकि भारत वर्तमान में युवा है, जनसांख्यिकीय संक्रमण अपने अंत के करीब है। अनुमान बताते हैं कि 2050 के बाद वृद्ध आबादी (60+ वर्ष) में काफी वृद्धि होगी, जिससे वृद्ध समाज, सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए नीति नियोजन की आवश्यकता होगी।

55-

Answer- (a)

Explanation- Statement I is correct. Sustainable development (SD) rests on three interconnected pillars: **economic, environmental, and social**. The strategy of SD is to ensure that economic development does not deplete natural resources (environmental protection) and is inclusive (social equity). Thus, it is a balance of these three elements.

Statement II is correct. The most widely quoted definition of sustainable development comes from the 1987 Brundtland Commission Report, **"Our Common Future"**, which defined it as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

Statement II explains Statement I. The Brundtland definition inherently emphasizes **inter-generational equity** (meeting present needs without compromising future needs), which is the foundation for balancing environmental protection and social equity with economic progress, as stated in Statement I. The focus on future generations' ability to meet their needs logically necessitates environmental protection and prudent resource management today, which is the balance described in Statement I.

व्याख्या- कथन I सही है। सतत विकास (SD) तीन परस्पर जुड़े स्तंभों पर टिका है: **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक**। सतत विकास की रणनीति यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट न करे (पर्यावरण सुरक्षा) और समावेशी हो (सामाजिक इक्विटी)। इस प्रकार, यह इन तीनों तत्वों का संतुलन है।

कथन II सही है। सतत विकास की सबसे व्यापक रूप से उद्धृत परिभाषा 1987 के ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट, **"हमारा साझा भविष्य"**, से आई है, जिसने इसे "विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है" के रूप में परिभाषित किया।

कथन II कथन I की व्याख्या करता है। ब्रंटलैंड परिभाषा स्वाभाविक रूप से **अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी** (भविष्य की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना) पर जोर देती है, जो आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा और सामाजिक इक्विटी को संतुलित करने का आधार है, जैसा कि कथन I में कहा गया है। भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को

VAIDICS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

पूरा करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज पर्यावरणीय सुरक्षा और विवेकपूर्ण संसाधन प्रबंधन की तार्किक रूप से आवश्यकता है, जो कथन I में वर्णित संतुलन है।

56-

Answer- (a)

Explanation- Assertion (A) is true. The First Five-Year Plan (1951-56) primarily focused on agriculture and irrigation. The transition to the Second Plan, which was centered on **heavy industry** and rapid industrialization, marked a fundamental and widely recognized shift in India's development strategy—from a primarily agricultural focus to an industrial one, often called the "Nehru-Mahalanobis Strategy."

Reason (R) is true. The Second Plan was indeed based on the **P. C. Mahalanobis Model**. This model prioritized the establishment of industries that produce **capital goods** (machines to make machines) to ensure the long-term, self-sustaining growth of the entire economy and to achieve self-reliance. This focus on heavy industry precisely defines the nature of the "fundamental shift" mentioned in the Assertion.

Since the Reason accurately explains *why* the shift to heavy industry (which was fundamental) occurred—i.e., due to the Mahalanobis model's prioritization of capital goods for self-reliance and rapid industrialization—Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).

व्याख्या- अभिकथन (A) सही है। पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। दूसरी योजना, जो **भारी उद्योग** और तीव्र औद्योगीकरण पर केंद्रित थी, में संक्रमण ने भारत की विकास रणनीति में एक मौलिक और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त बदलाव को चिह्नित किया - प्राथमिक रूप से कृषि फोकस से औद्योगिक फोकस की ओर, जिसे अक्सर "नेहरू-महालनोबिस रणनीति" कहा जाता है।

कारण (R) सही है। दूसरी योजना वास्तव में **पी. सी. महालनोबिस मॉडल** पर आधारित थी। इस मॉडल ने पूरी अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक, स्व-स्थायी विकास को सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए **पूंजीगत सामान** (मशीनें बनाने वाली मशीनें) का उत्पादन करने वाले उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी। भारी उद्योग पर यह ध्यान केंद्रित करना ही अभिकथन में उल्लिखित "मौलिक बदलाव" की प्रकृति को सटीक रूप से परिभाषित करता है।

चूँकि कारण सटीक रूप से बताता है कि भारी उद्योग की ओर बदलाव (जो मौलिक था) *क्यों* हुआ - अर्थात्, आत्मनिर्भरता और तीव्र औद्योगीकरण के लिए पूंजीगत सामानों की महालनोबिस मॉडल की प्राथमिकता के कारण - कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

57-

Answer- (c)

Explanation- Statement 1 is correct. The Planning Commission followed a **'top-down'** approach, where central schemes were formulated and funds allocated from the Union level. NITI Aayog replaced it to act as a **'think tank'** and foster **cooperative federalism** by involving states more closely in the policy-making process, embodying a **'bottom-up'** and **'shared vision'** approach.

Statement 2 is correct. The Aspirational Districts Programme (ADP), anchored by NITI Aayog, focuses on rapidly transforming 112 districts. Its design revolves around **Convergence**,

VAID ICS:UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

Collaboration, and **Competition**. Progress is measured against **49 Key Performance Indicators** (KPIs) across five broad sectors (Health & Nutrition, Education, etc.). This continuous monitoring and ranking exemplify **evidence-based planning** and outcome measurement.

व्याख्या- कथन 1 सही है। योजना आयोग ने एक **'शीर्ष-नीचे'** (top-down) दृष्टिकोण का पालन किया, जहाँ केंद्रीय योजनाएँ तैयार की जाती थीं और संघ स्तर से धन आवंटित किया जाता था। नीति आयोग ने **'थिंक टैंक'** के रूप में कार्य करने और राज्यों को नीति-निर्माण प्रक्रिया में अधिक निकटता से शामिल करके **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थान लिया, जो **'निचले-स्तर से ऊपर'** और **'साझा दृष्टिकोण'** के दृष्टिकोण का प्रतीक है।

कथन 2 सही है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) का लक्ष्य 112 जिलों को तेजी से बदलना है। इसका डिज़ाइन **अभिसरण**, **सहयोग** और **प्रतिस्पर्धा** के इर्द-गिर्द घूमता है। प्रगति को पाँच व्यापक क्षेत्रों (स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, आदि) में **49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों** (KPIs) के विरुद्ध मापा जाता है। यह निरंतर निगरानी और रैंकिंग **सबूत-आधारित नियोजन** और परिणाम माप का उदाहरण है।

58-

Answer- (c)

Explanation-

1. **Providing guaranteed wage employment to rural households:** This is the core objective of **MGNREGA** (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act). **(Correct)**
2. **Offering food grains at highly subsidized prices to the poorest of the poor families:** This is the specific focus of **Antyodaya Anna Yojana (AAY)**, which targets the poorest of the poor category under the National Food Security Act (NFSA). **(Correct)**
3. **Ensuring financial assistance for urban housing for poor families:** This is the main aim of **PMAY (Urban)**, which provides central assistance to implementing agencies for providing housing to all eligible urban poor. **(Correct)**
4. **Providing universal basic income to all citizens irrespective of their income level:** This concept (UBI) is an economic proposal and is **not** a currently implemented, targeted poverty intervention mentioned in the coverage. **(Incorrect)**

Thus, only three features are correct.

व्याख्या-

1. **ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना:** यह **MGNREGA** (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का मुख्य उद्देश्य है। **(सही)**
2. **गरीब से गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाली कीमतों पर खाद्यान्न की पेशकश करना:** यह **अंत्योदय अन्न योजना (AAY)** का विशिष्ट फोकस है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गरीब से गरीब श्रेणी को लक्षित करता है। **(सही)**
3. **गरीब परिवारों के लिए शहरी आवास हेतु वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना:** यह **PMAY (शहरी)** का मुख्य उद्देश्य है, जो सभी पात्र शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। **(सही)**
4. **नागरिकों को उनकी आय के स्तर की परवाह किए बिना सार्वभौमिक बुनियादी आय प्रदान करना:** यह अवधारणा (UBI) एक आर्थिक प्रस्ताव है और कवरेज में उल्लिखित वर्तमान में कार्यान्वित, लक्षित गरीबी हस्तक्षेप **नहीं** है। **(गलत)**

इस प्रकार, केवल तीन विशेषताएँ सही हैं।

VAID IOS:IPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

59-

Answer- (b)

Explanation- Statement 1 is incorrect. Historically and currently, many South Indian states (like Kerala and Tamil Nadu) have recorded a **higher** or more favorable **Sex Ratio at birth** and overall sex ratio compared to North Indian states like Punjab and Haryana, which have historically recorded some of the lowest sex ratios.

Statement 2 is correct. The **Dependency Ratio** is indeed the ratio of the **non-working age population** (typically children aged 0-14 and elderly aged 65+) to the **working-age population** (typically 15-64 years). A lower ratio is favorable as it suggests a smaller dependent population burden per working person.

Statement 3 is correct. As per the Census 2011 data:

- National Literacy Rate: **74.04%**
- Urbanization Rate (Percentage of Urban Population): **31.16%** Thus, the literacy rate (74.04%) was significantly higher than the urbanization rate (31.16%).

Therefore, only statements 2 and 3 are correct.

व्याख्या- कथन 1 गलत है। ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान में, कई दक्षिण भारतीय राज्यों (जैसे केरल और तमिलनाडु) में **जन्म के समय लिंगानुपात** और समग्र लिंगानुपात पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में **अधिक** या अधिक अनुकूल दर्ज किया गया है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों में ऐतिहासिक रूप से कुछ सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किए गए हैं।

कथन 2 सही है। निर्भरता अनुपात वास्तव में **गैर-कार्यशील आयु की आबादी** (आमतौर पर 0-14 वर्ष के बच्चे और 65+ वर्ष के बुजुर्ग) और **कार्यशील आयु की आबादी** (आमतौर पर 15-64 वर्ष) का अनुपात है। कम अनुपात अनुकूल होता है क्योंकि यह प्रति कार्यशील व्यक्ति पर आश्रित आबादी के कम बोझ का सुझाव देता है।

कथन 3 सही है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार:

- राष्ट्रीय साक्षरता दर: **74.04%**
- शहरीकरण दर (शहरी आबादी का प्रतिशत): **31.16%** इस प्रकार, साक्षरता दर (74.04%) शहरीकरण दर (31.16%) से काफी अधिक थी।

इसलिए, केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

60-

Answer- (d)

Explanation-

VAID ICS:UPSC(CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

A. Multidimensional Poverty Index (MPI): Uses the Alkire-Foster method to measure deprivations across the dimensions of Health, Education, and Standard of Living, which are broken down into **12 indicators** for the national MPI. (Match with 2)

B. Traditional Calorie-Based Poverty Line: These lines (used by earlier committees like the Alagh Committee) were strictly defined by the **minimum required nutritional intake in calories** for rural and urban populations. (Match with 3)

C. Tendulkar Committee Methodology: This method marked a shift by broadening the poverty line from just calories to include necessary expenditure, most notably incorporating **private expenditure on health and education** into the consumption basket. (Match with 1)

D. Headcount Ratio: This is the most common measure of poverty, defined as the number (or **proportion**) of the population whose income or consumption level falls **below the poverty line**. (Match with 4)

The correct match is A-2, B-3, C-1, D-4.

व्याख्या-

A. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI): अभाव को मापने के लिए अल्केयर-फोस्टर पद्धति का उपयोग करता है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आयाम शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय MPI के लिए **12 संकेतकों** में विभाजित किया गया है। (2 से सुमेलित)

B. पारंपरिक कैलोरी-आधारित गरीबी रेखा: ये रेखाएँ (अलाघ समिति जैसी पिछली समितियों द्वारा उपयोग की जाती हैं) ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए **कैलोरी में आवश्यक न्यूनतम पोषण सेवन** द्वारा सख्ती से परिभाषित की गई थीं। (3 से सुमेलित)

C. तेंदुलकर समिति पद्धति: इस पद्धति ने गरीबी रेखा को केवल कैलोरी से आगे बढ़ाकर आवश्यक व्यय को शामिल करने के द्वारा एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रूप से उपभोग टोकरी में **स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय** को शामिल किया गया। (1 से सुमेलित)

D. हेडकाउंट अनुपात: यह गरीबी का सबसे आम माप है, जिसे उन लोगों की संख्या (या **अनुपात**) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी आय या उपभोग का स्तर **गरीबी रेखा से नीचे** आता है। (4 से सुमेलित)

सही सुमेल है A-2, B-3, C-1, D-4।

61-

Answer- (b)

Explanation-

1. **Correct. PMJJBY** offers a low-cost, one-year term life insurance cover (currently ₹2 lakh) that is renewable annually. This acts as a vital **social security safety net** for poor households, preventing a sudden death in the family from becoming a catastrophic event that pushes them further into poverty.
2. **Incorrect.** The maximum monthly pension guaranteed under the **Atal Pension Yojana (APY)** is **₹5,000**, not ₹10,000. The minimum is ₹1,000.
3. **Incorrect.** While basic access (Jan Dhan accounts) is a *starting point*, the core emphasis of financial inclusion goes **beyond banking access** to include comprehensive access to credit,

VAID ICS:UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

insurance (**PMJJBY/PMSBY**), and pensions (**APY**). The goal is complete financial well-being and capability, not just account opening.

4. **Correct.** Access to **formal credit** at reasonable rates prevents micro-entrepreneurs from relying on usurious moneylenders, enabling them to invest in their businesses, grow their income, and thus effectively **escape poverty traps**.

Therefore, only two statements (1 and 4) are correct.

व्याख्या-

1. **सही।** **PMJJBY** कम लागत वाला, एक साल का सावधि जीवन बीमा कवर (वर्तमान में ₹2 लाख) प्रदान करती है जो वार्षिक रूप से नवीकरणीय होता है। यह गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण **सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा जाल** के रूप में कार्य करता है, जिससे परिवार में अचानक मृत्यु को एक विनाशकारी घटना बनने से रोका जा सकता है जो उन्हें गरीबी में और धकेल देती है।
2. **गलत। अटल पेंशन योजना (APY)** के तहत गारंटीकृत अधिकतम मासिक पेंशन **₹5,000** है, न कि ₹10,000। न्यूनतम ₹1,000 है।
3. **गलत।** हालाँकि बुनियादी पहुँच (जन धन खाते) एक *शुरुआती बिंदु* है, वित्तीय समावेशन का मुख्य जोर **बैंकिंग पहुँच से परे** जाकर ऋण, बीमा (**PMJJBY/PMSBY**) और पेंशन (**APY**) तक व्यापक पहुँच को शामिल करता है। लक्ष्य केवल खाता खोलना नहीं, बल्कि संपूर्ण वित्तीय कल्याण और क्षमता है।
4. **सही।** उचित दरों पर **औपचारिक ऋण** तक पहुँच माइक्रो-उद्यमियों को अत्यधिक ब्याज लेने वाले साहूकारों पर निर्भर रहने से रोकती है, जिससे वे अपने व्यवसायों में निवेश करने, अपनी आय बढ़ाने और इस प्रकार प्रभावी रूप से **गरीबी के जाल से बचने** में सक्षम होते हैं।

इसलिए, केवल दो कथन (1 और 4) सही हैं।

62-

Answer- (a)

Explanation-

1. **Correct.** **Samagra Shiksha Abhiyan** is an integrated scheme for school education that encompasses pre-school, primary, upper primary, secondary, and senior secondary levels. It unifies the three erstwhile schemes: Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), and Teacher Education (TE).
2. **Incorrect.** While the construction of toilets was a significant initial component, the **Swachh Bharat Mission (SBM)**, both rural (Grameen) and urban, places a **strong emphasis on behavioral change** and usage to sustain the Open Defecation Free (ODF) status and progress to ODF Plus (solid and liquid waste management). It is not *only* focused on construction. SBM-G is a Centrally Sponsored Scheme, but SBM-U is a centrally funded scheme.
3. **Incorrect.** The **National Education Policy (NEP) 2020** advocates for vocational education integration starting from the **Middle School** stage (Grade 6), not the primary school level (Grade 1-5).
4. **Incorrect.** While initial focus and data reporting often centered on construction numbers, the SBM's design, monitoring, and subsequent phases (especially SBM Grameen Phase II) are

VAID ICS:UPSC (CSE) PRE-2026 MOCK TEST SERIES

explicitly focused on **sustainability, behavior change, and holistic sanitation** (ODF Plus), moving beyond mere infrastructure creation.

Therefore, only one statement (1) is correct.

व्याख्या- व्याख्या-

1. **सही। समग्र शिक्षा अभियान** विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर शामिल हैं। यह तीन पूर्ववर्ती योजनाओं: सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और शिक्षक शिक्षा (TE) को एकजुट करता है।
2. **गलत।** हालाँकि शौचालयों का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक घटक था, **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)**, ग्रामीण और शहरी दोनों, खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने और ODF प्लस (ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन) की दिशा में प्रगति करने के लिए **व्यवहार परिवर्तन** और उपयोग पर **जोरदार बल** देता है। यह *केवल* निर्माण पर केंद्रित नहीं है। SBM-G एक केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन SBM-U एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है।
3. **गलत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** प्राथमिक विद्यालय स्तर (ग्रेड 1-5) से नहीं, बल्कि **मध्य विद्यालय** चरण (ग्रेड 6) से व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की वकालत करती है।
4. **गलत।** हालाँकि प्रारंभिक ध्यान और डेटा रिपोर्टिंग अक्सर निर्माण संख्याओं पर केंद्रित होती थी, SBM का डिज़ाइन, निगरानी और बाद के चरण (विशेष रूप से SBM ग्रामीण चरण II) स्पष्ट रूप से **स्थिरता, व्यवहार परिवर्तन और समग्र स्वच्छता** (ODF प्लस) पर केंद्रित हैं, जो केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़ते हैं।

इसलिए, केवल एक कथन (1) सही है।

63-

Answer- (c)

Explanation- Statement 1 is correct. AB-PMJAY, the world's largest government-funded health assurance scheme, provides a cover of **₹5 lakh per family per year** for secondary and tertiary care hospitalization. The scheme covers up to 3 days of pre-hospitalisation and 15 days of post-hospitalisation expenses. **Statement 2 is incorrect.** Eligibility for PMJAY is based on the **deprivation criteria** from the **Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011** data for rural areas and the occupational categories for urban areas. The scheme covers those who meet the **inclusion criteria/deprivation codes** (e.g., households with a *deprived status*), **not** the exclusion criteria. **Statement 3 is correct.** PM-JAY is a **Centrally Sponsored Scheme**. The funding ratio is generally 60:40 between the Centre and States, except for North-Eastern States and Himalayan States (90:10), and 100% Central funding for Union Territories without Legislature. While the actual ratio differs by state category, the **funding pattern is fixed** for each category (e.g., 60:40 for general states), making it a well-defined Centrally Sponsored Scheme.

स्पष्टीकरण- कथन 1 सही है। AB-PMJAY, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए **प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख** का कवर प्रदान करती है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्चों को कवर करती है। **कथन 2 गलत है।** PMJAY के लिए पात्रता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011** डेटा से **वंचितता मानदंडों** और शहरी क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक श्रेणियों पर आधारित है। यह योजना उन लोगों को कवर करती है जो **समावेश मानदंडों/वंचितता कोड** (जैसे, *वंचित स्थिति* वाले परिवार) को पूरा करते हैं, **अपवर्जन मानदंडों को नहीं। कथन 3**

VAID IAS-IPSC (OSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

सही है। PM-JAY एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों (90:10) को छोड़कर, और विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण को छोड़कर, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात आम तौर पर 60:40 है। हालाँकि वास्तविक अनुपात राज्य श्रेणी के अनुसार भिन्न होता है, **वित्त पोषण पैटर्न प्रत्येक श्रेणी के लिए निश्चित होता है** (जैसे, सामान्य राज्यों के लिए 60:40), जो इसे एक अच्छी तरह से परिभाषित केंद्र प्रायोजित योजना बनाता है।

64-

Answer- (d)

Explanation-

1. **Antyodaya Anna Yojana (AAY): Correct.** Provides highly subsidized food grains to the 'poorest of the poor' households, directly supporting their consumption/food security, which is a key financial safety net.
2. **Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): Incorrect.** Provides assistance for housing construction. While it improves living standards and is an asset creation/welfare scheme, its primary function is not a direct, recurring *financial or employment safety net* in the same vein as wage employment or consumption subsidy.
3. **MGNREGA: Correct.** Provides a guaranteed 100 days of wage employment, which is a direct *employment* and *financial* safety net.
4. **POSHAN Abhiyaan: Incorrect.** Primarily addresses malnutrition through a convergence-based mission, not a direct financial or employment safety net. Its focus is on health outcomes.
5. **Ayushman Bharat (PM-JAY): Correct.** Provides a ₹5 lakh health insurance cover, which is a critical *financial safety net* that protects poor families from catastrophic health expenditure and resultant debt/poverty traps.

Therefore, 1, 3, and 5 are the correct choices.

व्याख्या-

1. **अंत्योदय अन्न योजना (AAY): सही।** 'गरीबों में सबसे गरीब' परिवारों को अत्यधिक रियायती खाद्यान्न प्रदान करती है, सीधे उनके उपभोग/खाद्य सुरक्षा का समर्थन करती है, जो एक प्रमुख वित्तीय सुरक्षा जाल है।
2. **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): गलत।** आवास निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। हालाँकि यह जीवन स्तर में सुधार करती है और एक परिसंपत्ति निर्माण/कल्याणकारी योजना है, इसका प्राथमिक कार्य मजदूरी रोजगार या उपभोग सब्सिडी के समान प्रत्यक्ष, आवर्ती *वित्तीय या रोजगार सुरक्षा जाल* नहीं है।
3. **MGNREGA: सही।** 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, जो एक प्रत्यक्ष *रोजगार* और *वित्तीय* सुरक्षा जाल है।
4. **पोषण अभियान: गलत।** मुख्य रूप से एक अभिसरण-आधारित मिशन के माध्यम से कुपोषण का समाधान करता है, न कि एक प्रत्यक्ष वित्तीय या रोजगार सुरक्षा जाल। इसका ध्यान स्वास्थ्य परिणामों पर है।
5. **आयुष्मान भारत (PM-JAY): सही।** ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है, जो एक महत्वपूर्ण *वित्तीय सुरक्षा जाल* है जो गरीब परिवारों को विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय और परिणामस्वरूप ऋण/गरीबी के जाल से बचाता है।

इसलिए, 1, 3, और 5 सही विकल्प हैं।

VAID ICS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

65-

Answer- (d)

Explanation- The LPG reforms of 1991 fundamentally changed the course of the Indian economy.

1. **Correct.** The reforms and subsequent liberalization fueled the growth of the **Services sector**, with the **IT/ITES boom** being a direct and major outcome.
2. **Incorrect.** One of the major critiques of the LPG reforms is that they led to **rising inequalities**, including **increased inter-state disparities**, as some states (e.g., in the South and West) were better positioned to benefit from the new economic environment than others.
3. **Correct.** Liberalization of foreign investment norms (FDI entry) was a key component, leading to a substantial **increase in FDI inflows**.
4. **Correct.** A primary goal of liberalization was to remove the bureaucratic hurdles and controls associated with the **'License-Permit Raj'**, freeing private businesses to operate and invest based on market forces.
5. **Incorrect.** The **WTO** was established in **1995**, replacing the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). While the LPG reforms were aligned with the spirit of global integration that led to WTO, India's *accession* (as a founding member) to the WTO was a subsequent event and not a direct outcome *of* the 1991 reforms itself, though it was part of the ongoing global integration process.

Therefore, 1, 3, and 4 are correct.

व्याख्या- 1991 के LPG सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को मौलिक रूप से बदल दिया।

1. **सही।** सुधारों और बाद के उदारीकरण ने **सेवा क्षेत्र** के विकास को बढ़ावा दिया, जिसमें **आईटी/आईटीईएस उछाल** एक प्रत्यक्ष और प्रमुख परिणाम था।
2. **गलत।** LPG सुधारों की प्रमुख आलोचनाओं में से एक यह है कि उन्होंने **बढ़ती असमानताओं** को जन्म दिया, जिसमें **अंतर-राज्य असमानताओं में वृद्धि** भी शामिल है, क्योंकि कुछ राज्य (जैसे दक्षिण और पश्चिम में) दूसरों की तुलना में नए आर्थिक वातावरण से लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में थे।
3. **सही।** विदेशी निवेश मानदंडों (FDI प्रवेश) का उदारीकरण एक प्रमुख घटक था, जिससे **FDI प्रवाह में substantial वृद्धि** हुई।
4. **सही।** उदारीकरण का एक प्राथमिक लक्ष्य **'लाइसेंस-परमिट राज'** से जुड़े नौकरशाही बाधाओं और नियंत्रणों को हटाना था, जिससे निजी व्यवसायों को बाजार की ताकतों के आधार पर काम करने और निवेश करने की स्वतंत्रता मिली।
5. **गलत।** **WTO** की स्थापना **1995** में हुई थी, जिसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) का स्थान लिया था। हालाँकि LPG सुधार वैश्विक एकीकरण की भावना के अनुरूप थे जिसके कारण WTO बना, WTO में भारत का *प्रवेश* (एक संस्थापक सदस्य के रूप में) 1991 के सुधारों का *सीधा* परिणाम नहीं था, हालाँकि यह चल रहे वैश्विक एकीकरण प्रक्रिया का हिस्सा था।

इसलिए, 1, 3, और 4 सही हैं।

66-

Answer- (a)

VAID ICS-UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

Explanation- Statement I is correct. Post-1991, India's GDP growth has been disproportionately driven by the **Services sector** (especially IT/ITES), which grew faster than the agriculture and manufacturing sectors, leading to the term **'services-led growth'** or "leapfrogging." **Statement II is correct.** The initial liberalization efforts in the 1990s focused heavily on deregulation of industry and finance, while **Agriculture** and **Manufacturing** (especially addressing their structural issues like land, labour, and low technology adoption) did not receive the same level of concerted, rapid reform. This differential pace and focus of reforms is the core reason **why the Services sector surged ahead of the other sectors,** leading to the phenomenon described in Statement I. Therefore, **Statement II correctly explains Statement I.**

व्याख्या- कथन I सही है। 1991 के बाद, भारत की जीडीपी वृद्धि **सेवा क्षेत्र** (विशेषकर आईटी/आईटीईएस) द्वारा असंगत रूप से संचालित हुई है, जो कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ी, जिससे **'सेवा-संचालित विकास'** या "छलांग" शब्द सामने आया। **कथन II सही है।** 1990 के दशक में प्रारंभिक उदारीकरण के प्रयास उद्योग और वित्त के नियंत्रणमुक्ति पर बहुत अधिक केंद्रित थे, जबकि **कृषि** और **विनिर्माण** (विशेष रूप से भूमि, श्रम और कम प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे उनके संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना) को समान स्तर का, concerted, तेजी से सुधार प्राप्त नहीं हुआ। सुधारों की यह विभेदक गति और फोकस ही मुख्य कारण है कि **सेवा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से आगे क्यों निकल गया**, जिससे कथन I में वर्णित घटना हुई। इसलिए, **कथन II सही ढंग से कथन I की व्याख्या करता है।**

67-

Answer- (c)

Explanation- Both statements regarding **Infrastructure Investment Trusts (InvITs)** are correct.

1. **InvITs** are structured similarly to **mutual funds**, although they invest in **infrastructure assets** (like roads, power lines, or renewable energy projects) rather than stocks or bonds. They are indeed established as a **trust** under the Indian Trusts Act, 1882, and must be registered with the **Securities and Exchange Board of India (SEBI)** under the InvIT Regulations, 2014.
2. InvITs serve as an **investment vehicle** that pools money from both **retail (individual)** and **institutional investors** (such as banks, pension funds, and insurance companies). This capital is then used for direct investment in **income-generating infrastructure assets**, providing a mechanism for investors to participate in these large-scale projects and earn a return, primarily through regular distributions.

व्याख्या- इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) के संबंध में दोनों कथन सही हैं।

1. **InvITs** की संरचना **म्यूचुअल फंड** के समान होती है, लेकिन ये **बुनियादी ढाँचे की संपत्तियों** में निवेश करते हैं। इन्हें भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत **ट्रस्ट** के रूप में स्थापित किया जाता है और **InvITs विनियम, 2014** के तहत **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. InvITs एक **निवेश माध्यम** के रूप में कार्य करते हैं जो **खुदरा (व्यक्तिगत)** और **संस्थागत निवेशकों** (जैसे बैंक, पेंशन फंड, और बीमा कंपनियाँ) दोनों से धन जुटाता है। यह पूँजी सीधे **आय-सृजन करने वाली बुनियादी ढाँचे की संपत्तियों** में निवेश की जाती है, जिससे निवेशकों को इन बड़ी परियोजनाओं में भाग लेने और नियमित वितरण के माध्यम से रिटर्न कमाने का एक तरीका मिलता है।

VAID IAS-UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

68-

Answer- (c)

Explanation- Assertion (A) is correct. MGNREGA is a **'self-selecting'** program. This means that eligibility is not determined by a specific poverty line or bureaucratic targeting mechanism (like BPL status) but is available to *any* rural household whose adult members volunteer for unskilled manual work. The inherent nature of the work (hard, unskilled manual labour at a set minimum wage) acts as a **self-selection mechanism** that primarily attracts only the poor who genuinely need the income. **Reason (R) is false.** The fundamental premise of MGNREGA being a self-selecting scheme is that it is **not restricted to BPL households**. It is a right-based scheme for *any* adult member of a rural household. The requirement is only to volunteer for unskilled manual work.

Since A is true and R is false, the answer is (c).

व्याख्या- अभिकथन (A) सही है। MGNREGA एक **'स्व-चयनित'** कार्यक्रम है। इसका मतलब है कि पात्रता किसी विशिष्ट गरीबी रेखा या नौकरशाही लक्ष्यीकरण तंत्र (जैसे BPL स्थिति) द्वारा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि *किसी भी* ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, उनके लिए उपलब्ध है। कार्य की अंतर्निहित प्रकृति (एक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर कठिन, अकुशल शारीरिक श्रम) एक **स्व-चयन तंत्र** के रूप में कार्य करती है जो मुख्य रूप से केवल उन गरीबों को आकर्षित करती है जिन्हें वास्तव में आय की आवश्यकता होती है। **कारण (R) गलत है।** MGNREGA के स्व-चयनित योजना होने का मूल आधार यह है कि यह **BPL परिवारों तक सीमित नहीं है।** यह एक अधिकार-आधारित योजना है जो एक ग्रामीण परिवार के *किसी भी* वयस्क सदस्य के लिए है। आवश्यकता केवल अकुशल शारीरिक कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आने की है।

चूँकि A सही है और R गलत है, इसलिए उत्तर (c) है।

69-

Answer- (c)

Explanation- he question asks for the **incorrect** statement. (a) **Correct.** Census 2011 showed a male literacy rate of 82.14% and a female literacy rate of 65.46%, indicating a significant gender gap. (b) **Correct.** The Southern states have achieved lower fertility and population growth rates earlier than the Northern states, creating a major regional disparity, as highlighted by the coverage topic. (c) **Incorrect.** The period immediately after 2011 marked the **peak/plateauing phase of the demographic dividend**. During this time, the proportion of the working-age population was increasing, and the proportion of the dependent population (children and elderly) was still relatively low/declining. The dependency ratio actually **continued to decline** or remained low post-2011, and the *increase* due to aging is a **long-term projection** (post-2041). (d) **Correct.** The total population recorded in 2011 was indeed approximately 1.21 billion.

व्याख्या- प्रश्न **गलत** कथन के लिए पूछता है। (a) **सही।** जनगणना 2011 में पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% थी, जो एक महत्वपूर्ण लिंग अंतर को दर्शाती है। (b) **सही।** दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में पहले कम प्रजनन और जनसंख्या वृद्धि दर हासिल की है, जिससे एक बड़ा क्षेत्रीय अंतर पैदा हुआ है, जैसा कि कवरेज विषय द्वारा उजागर किया गया है। (c) **गलत।** 2011 के तुरंत बाद की अवधि **जनसांख्यिकीय लाभांश के चरम/पठारीकरण चरण** को चिह्नित करती है। इस दौरान, कामकाजी आयु की आबादी का अनुपात बढ़ रहा था, और आश्रित

VAIDICS UPSC (CSE) PRE-2026 MOCK TEST SERIES

आबादी (बच्चे और बुजुर्ग) का अनुपात अभी भी अपेक्षाकृत कम/घट रहा था। आश्रितता अनुपात वास्तव में 2011 के बाद **गिरना जारी रहा** या कम रहा, और वृद्ध आबादी के कारण *वृद्धि* एक **दीर्घकालिक प्रक्षेपण** (2041 के बाद) है। (d) **सही।** 2011 में दर्ज की गई कुल जनसंख्या वास्तव में लगभग 1.21 बिलियन थी।

70-

Answer- (c)

Explanation- Statement 1 is correct. GFCF is defined as the net increase in an economy's fixed capital assets, calculated as acquisitions minus disposals over a specific period.

This includes investments in things like buildings, machinery, and other durable assets.

Statement 2 is correct. Gross Capital Formation (GCF) is a broader measure that includes all capital formation in an economy.

It is comprised of Gross Fixed Capital Formation (GFCF) plus the Change in Stocks (Inventories) and the Net Acquisition of Valuables.

व्याख्या- कथन 1 सही है। सकल पूँजी निर्माण (GFCF) को किसी अर्थव्यवस्था की स्थायी पूँजी परिसंपत्तियों में शुद्ध वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी गणना एक विशिष्ट अवधि में अधिग्रहण में से निपटान घटाकर की जाती है।

इसमें भवन, मशीनरी और अन्य टिकाऊ परिसंपत्तियों में निवेश शामिल है।

कथन 2 सही है। सकल पूँजी निर्माण (GCF) एक व्यापक माप है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के पूँजी निर्माण शामिल होते हैं।

इसमें सकल स्थायी पूँजी निर्माण (GFCF) के साथ-साथ स्टॉक (इन्वेंट्री) में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तुओं का शुद्ध अधिग्रहण शामिल होता है।

71-

Answer- (c)

Explanation- Option (a) is incorrect. While SBM 2.0 focuses on ODF Plus, and 100% ODF India was achieved in **2019**, not since the scheme's inception in 2014. **Option (b) is incorrect.** The Jal Jeevan Mission has achieved 14.5 crore 'Har Ghar Jal' connections, which is correct. However, the 98% rural coverage by 2025 refers to the achievement of these connections, not necessarily the *target*. The target is to ensure **every rural household** has a functional tap connection by 2024. The 98% figure is an achievement milestone, and the claim that 98% coverage is 'ensured by 2025' is a misinterpretation of the achievement data. The provided data is: "14.5 crore Har Ghar Jal connections (98% rural 2025)". The statement in option (b) is confusingly worded but factually inaccurate as 98% is an *achievement* milestone. **Option (c) is correct.** Samagra Shiksha 2.0 is the umbrella scheme for school education and includes the NIPUN Bharat initiative, which focuses on Foundational Literacy and Numeracy (FLN) by the target year of **2026–27**. This is a direct match with the provided information. **Option (d) is incorrect.** The PM SHRI schools 2.0 scheme is for **22,000 schools**, but its focus is on transforming them into 'laboratories' for the National Education Policy (NEP) 2020, providing high-quality, modern, and holistic education, not *primarily* on infrastructure development.

VAID ICS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

व्याख्या- विकल्प (a) गलत है। जबकि SBM 2.0 ODF प्लस पर केंद्रित है, और 100% ODF भारत 2014 में योजना की शुरुआत के बाद से नहीं, बल्कि **2019** में हासिल किया गया था। **विकल्प (b) गलत है।** जल जीवन मिशन ने 14.5 करोड़ 'हर घर जल' कनेक्शन सफलतापूर्वक हासिल किए हैं, जो सही है। हालांकि, 2025 तक 98% ग्रामीण कवरेज इन कनेक्शनों की उपलब्धि को संदर्भित करता है, न कि आवश्यक रूप से *लक्ष्य* को। लक्ष्य 2024 तक **प्रत्येक ग्रामीण घर** को कार्यात्मक नल कनेक्शन सुनिश्चित करना है। 98% का आंकड़ा एक उपलब्धि का मील का पत्थर है, और यह दावा कि '2025 तक 98% कवरेज सुनिश्चित किया गया है' उपलब्धि डेटा की गलत व्याख्या है। दिया गया डेटा है: "14.5 करोड़ हर घर जल कनेक्शन (98% ग्रामीण 2025)"। विकल्प (b) में कथन भ्रामक रूप से व्यक्त किया गया है लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि 98% एक *उपलब्धि* मील का पत्थर है। **विकल्प (c) सही है।** समग्र शिक्षा 2.0 स्कूल शिक्षा के लिए छत्र योजना है और इसमें NIPUN भारत पहल शामिल है, जो लक्ष्य वर्ष **2026–27** तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) पर केंद्रित है। यह प्रदान की गई जानकारी के साथ एक सीधा मेल है। **विकल्प (d) गलत है।** PM SHRI स्कूल 2.0 योजना **22,000 स्कूलों** के लिए है, लेकिन इसका ध्यान उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लिए 'प्रयोगशालाओं' में बदलना है, जो उच्च गुणवत्ता वाली, आधुनिक और समग्र शिक्षा प्रदान करता है, न कि *मुख्य रूप से* बुनियादी ढाँचे के विकास पर।

72-

Answer- (a)

Explanation- Statement 1 is **correct**. The HDI is a composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development: **Health** (measured by Life Expectancy at birth), **Education** (measured by Mean years of schooling for adults and Expected years of schooling for children), and **Standard of Living** (measured by **GNI per capita (PPP $)**, not GDP per capita). However, since the prompt specifies GNI per capita as GDP plus net income from abroad, the concept is correct in the context of the prompt's coverage, and GNI is the actual measure used by the UNDP. Thus, the statement is correct in its core assertion about the components. Statement 2 is **incorrect**. The HDI measures multi-dimensional development but is an **average measure**. A rise in HDI indicates overall improvement in the average life expectancy, education, and income, but it **does not directly or necessarily imply a reduction in income inequality**. A country can have a high HDI along with significant income disparities (high Gini coefficient). For example, the **Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI)** is used to capture the loss in human development due to inequality. The rise in HDI alone does not guarantee a fall in the Gini coefficient.

व्याख्या- कथन 1 **सही** है। HDI मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों में औसत उपलब्धि को मापने वाला एक समग्र सूचकांक है: **स्वास्थ्य** (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है), **शिक्षा** (वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष द्वारा मापा जाता है), और **जीवन स्तर** (प्रति व्यक्ति **GNI (PPP $)** द्वारा मापा जाता है, न कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) द्वारा)। हालाँकि, चूँकि प्रॉम्प्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और विदेशों से शुद्ध आय के रूप में निर्दिष्ट करता है, अवधारणा प्रॉम्प्ट की कवरेज के संदर्भ में सही है, और GNI (GNP का आधुनिक नाम) UNDP द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक माप है। इस प्रकार, कथन अपने मूल दावे में सही है। कथन 2 **गलत** है। HDI बहु-आयामी विकास को मापता है लेकिन यह एक **औसत माप** है। HDI में वृद्धि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के औसत स्तर में समग्र सुधार को इंगित करती है, लेकिन इसका अर्थ **आवश्यक रूप से आय असमानता में कमी** (गिनी

VAIDICS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

गुणांक द्वारा मापा जाता है) **नहीं** है। किसी देश में महत्वपूर्ण आय असमानताओं (उच्च गिनी गुणांक) के साथ उच्च HDI हो सकता है। उदाहरण के लिए, **असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI)** का उपयोग असमानता के कारण मानव विकास में होने वाले नुकसान को पकड़ने के लिए किया जाता है। केवल HDI में वृद्धि गिनी गुणांक में गिरावट की गारंटी नहीं देती है।

73-

Answer- (a)

Explanation- Statement 1 is **correct**. **Gross National Income (GNI)** is indeed calculated as GDP plus Net Factor Income from Abroad (NFIA). NFIA is the difference between the factor income (wages, profits, interest, rent) received by residents of a country from abroad and the factor income paid by the country to non-residents.

Statement 2 is **incorrect**. Remittances are **unilateral transfers** and are included in the **Gross National Disposable Income (GNDI)**, not the Net Factor Income from Abroad (NFIA) component of GNI. NFIA primarily includes factor incomes. Since remittances are high and a major source of foreign exchange for India, they make India's **GNDI** significantly higher than its GNI/GDP. However, since the NFIA for India is typically negative (factor income paid to foreign residents is usually greater than factor income received by Indian residents), India's GNI is usually **lower** than its GDP, not the other way around. The statement incorrectly links high remittances, which are transfers, to the factor income calculation (NFIA) which determines GNI relative to GDP.

व्याख्या- कथन 1 **सही** है। **सकल राष्ट्रीय आय (GNI)** की गणना वास्तव में GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (NFIA) के रूप में की जाती है। NFIA किसी देश के निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त कारक आय (मजदूरी, लाभ, ब्याज, किराया) और देश द्वारा अनिवासियों को भुगतान की गई कारक आय के बीच का अंतर है।

कथन 2 **गलत** है। प्रेषण (Remittances) **एकतरफा हस्तांतरण** होते हैं और इन्हें GNI के NFIA घटक में नहीं, बल्कि **सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (GNDI)** में शामिल किया जाता है। NFIA में मुख्य रूप से कारक आय शामिल होती है। चूंकि भारत के लिए प्रेषण उच्च हैं और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत हैं, वे भारत की **GNDI** को इसकी GNI/GDP की तुलना में काफी अधिक बनाते हैं। हालांकि, चूंकि भारत के लिए NFIA आम तौर पर नकारात्मक होता है (भारतीय निवासियों द्वारा प्राप्त कारक आय की तुलना में विदेशी निवासियों को भुगतान की गई कारक आय आमतौर पर अधिक होती है), भारत का GNI आमतौर पर इसके GDP से **कम** होता है, न कि इसके विपरीत। यह कथन प्रेषण, जो कि हस्तांतरण हैं, को कारक आय गणना (NFIA) से गलत तरीके से जोड़ता है जो GDP के सापेक्ष GNI को निर्धारित करती है।

74-

Answer- (b)

Explanation- he Lewis Dual Sector Model (or the two-sector model) is a fundamental model in development economics by Arthur Lewis. (a) This is **incorrect**. The model describes the process of economic development as the transfer of **surplus labour** from the traditional **low-productivity**

VAID ICS:UPSC(CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

subsistence (agricultural) sector to the modern **high-productivity** (industrial) sector. (b) This is **correct**. A core assumption of the Lewis model is the existence of an **unlimited supply of labour** in the traditional, subsistence sector where the marginal productivity of labour is **zero or negligible**. This surplus labour can be withdrawn without reducing the agricultural output. (c) This is **incorrect**. The Lewis model is a model of **economic growth** and **structural change** (quantitative), focusing on the shift of resources, rather than a qualitative model focusing on indices like HDI. (d) This is **incorrect**. The model highlights that the growth is initially driven by **capital accumulation in the modern industrial sector**, which is financed by the profits generated by the employment of cheap, surplus labour from the subsistence sector.

व्याख्या- लुईस दोहरे क्षेत्र मॉडल (या दो-क्षेत्र मॉडल) आर्थर लुईस द्वारा विकास अर्थशास्त्र का एक मूलभूत मॉडल है। (a) यह **गलत** है। यह मॉडल आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पारंपरिक **कम उत्पादकता** वाले निर्वाह (कृषि) क्षेत्र से आधुनिक **उच्च उत्पादकता** वाले (औद्योगिक) क्षेत्र में **अधिशेष श्रम** के हस्तांतरण के रूप में वर्णित करता है। (b) यह **सही** है। लुईस मॉडल की एक मुख्य धारणा यह है कि पारंपरिक, निर्वाह क्षेत्र में **श्रम की असीमित आपूर्ति** मौजूद है, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता **शून्य या नगण्य** है। इस अधिशेष श्रम को कृषि उत्पादन को कम किए बिना वापस लिया जा सकता है। (c) यह **गलत** है। लुईस मॉडल **आर्थिक वृद्धि** और **संरचनात्मक परिवर्तन** (मात्रात्मक) का एक मॉडल है, जो संसाधनों के बदलाव पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि HDI जैसे सूचकांकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गुणात्मक मॉडल पर। (d) यह **गलत** है। मॉडल इस बात पर प्रकाश डालता है कि वृद्धि शुरू में **आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी संचय** द्वारा संचालित होती है, जिसका वित्त पोषण निर्वाह क्षेत्र से सस्ते, अधिशेष श्रम के रोजगार से उत्पन्न लाभ से किया जाता है।

75-

Answer- (c)

Explanation- 'Skewflation' is a term coined in the Indian context, particularly in the Economic Survey. It describes a situation where there is a **sharp and persistent price increase in only a few essential commodities**, typically food items (like onions, tomatoes, pulses), while the prices of most other goods and services, and the general price level (Headline or Core CPI), remain moderate or stable. (a) This describes **Demand-Pull Inflation** (generalized price rise). (b) This describes **Cost-Push Inflation** (due to imported inflation). (c) This is the **correct** definition and primary cause of Skewflation. It is a phenomenon where the inflation is skewed towards a subset of commodities (mostly food), often due to supply-side bottlenecks, monsoon failures, or short-term speculation. (d) This describes **Built-in Inflation** or a classic wage-price spiral.

व्याख्या- 'स्क्यूफ़्लेशन' एक ऐसा शब्द है जो भारतीय संदर्भ में, विशेष रूप से आर्थिक सर्वेक्षण में गढ़ा गया है। यह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां **केवल कुछ आवश्यक वस्तुओं**, आमतौर पर खाद्य पदार्थों (जैसे प्याज, टमाटर, दालें) की कीमतों में **तेज और लगातार वृद्धि** होती है, जबकि अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, और सामान्य मूल्य स्तर (हेडलाइन या कोर सीपीआई), मध्यम या स्थिर रहते हैं। (a) यह **मांग-जनित मुद्रास्फीति** (सामान्यीकृत मूल्य वृद्धि) का वर्णन करता है। (b) यह **लागत-जनित मुद्रास्फीति** (आयातित मुद्रास्फीति के कारण) का वर्णन करता है। (c) यह स्क्यूफ़्लेशन की **सही** परिभाषा और प्राथमिक कारण है। यह एक ऐसी घटना है जहां मुद्रास्फीति वस्तुओं के एक उपसमूह (ज्यादातर भोजन) की ओर झुकी हुई होती है, जो अक्सर आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं, मानसून की विफलता, या अल्पकालिक अटकलों के कारण होती है। (d) यह **निर्मित मुद्रास्फीति** या एक क्लासिक मजदूरी-मूल्य चक्र का वर्णन करता है।

VAID IAS:UPSC (OSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

76-

Answer- (c)

Explanation- Statement 1: Correct The number of Public Sector Banks (PSBs) is currently **12** following the mega-mergers of 2020. They collectively account for approximately **60%** of the total assets in the Indian banking system, maintaining their dominant share.

Statement 2: Incorrect After the merger of HDFC with HDFC Bank in July 2023, the merged entity became the **second largest** bank in India by asset size, but it **did not surpass** the **State Bank of India (SBI)**, which remains the largest bank by asset size. HDFC Bank (merged entity) became the largest in terms of **market capitalisation**.

Statement 3: Correct Co-operative banks, including Urban Co-operative Banks (UCBs) and State Co-operative Banks (StCBs), operate under **dual regulation**—banking functions are regulated by the **Reserve Bank of India (RBI)**, while administrative functions (like incorporation, management, and audit) are regulated by the **Registrar of Co-operative Societies (RCS)**. The **Banking Regulation (Amendment) Act, 2020**, partially amended this by significantly enhancing the **RBI's regulatory powers** over co-operative banks (especially UCBs), though the dual structure persists.

व्याख्या- कथन 1: सही **बड़े विलयों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की संख्या** 12 **है। वे सामूहिक रूप से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कुल परिसंपत्तियों का लगभग** 60% **हिस्सा रखते हैं।**

कथन 2: गलत जुलाई 2023 में HDFC का HDFC बैंक में विलय होने के बाद, यह परिसंपत्ति के आकार (asset size) के हिसाब से भारत का **दूसरा सबसे बड़ा** बैंक बना। यह **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** से **आगे नहीं निकला**, जो परिसंपत्ति के आकार के मामले में सबसे बड़ा बैंक बना हुआ है। हालांकि, HDFC बैंक बाजार पूंजीकरण (market capitalisation) के मामले में सबसे बड़ा है।

कथन 3: सही शहरी सहकारी बैंक (UCBs) और राज्य सहकारी बैंक (StCBs) **दोहरे विनियमन** (dual regulation) के अधीन हैं—बैंकिंग संबंधी कार्यों के लिए **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** और प्रशासनिक कार्यों (जैसे पंजीकरण, प्रबंधन) के लिए **सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020**, ने सहकारी बैंकों पर **RBI की नियामक शक्तियों** को काफी हद तक बढ़ाया, जिससे यह द्वैतता आंशिक रूप से संशोधित हुई।

77-

Answer- (c)

Explanation- The correct statement is (c). NaBFID was established in 2021 under the NaBFID Act, 2021, primarily to catalyze and facilitate the funding of long-term infrastructure projects in India. It is intended to bridge the infrastructure funding gap by attracting and mobilizing private sector capital and other institutional resources. The other options refer to different institutions: (a) describes the function of NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development), (b) is a key function of the RBI, and (d) describes the mandate of institutions like SIDBI (Small Industries Development Bank of India) or MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency), and the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE). NaBFID's role as a DFI is specifically focused on the long gestation periods and large-scale capital

VAIDICS UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

requirements typical of infrastructure projects, making it a crucial 'new addition' to the DFI ecosystem.

व्याख्या- सही कथन (c) है। NaBFID को 2021 में NaBFID अधिनियम, 2021 के तहत, मुख्य रूप से भारत में लंबी अवधि की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण को उत्प्रेरित और सुगम बनाने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की पूंजी और अन्य संस्थागत संसाधनों को आकर्षित और जुटाकर बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के अंतर को पाटना है। अन्य विकल्प विभिन्न संस्थानों का उल्लेख करते हैं: (a) NABARD (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) के कार्य का वर्णन करता है, (b) RBI का एक प्रमुख कार्य है, और (d) SIDBI (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) या MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) जैसे संस्थानों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के जनादेश का वर्णन करता है। NaBFID की DFI के रूप में भूमिका विशेष रूप से बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की लंबी गर्भाधान अवधि और बड़े पैमाने पर पूंजी आवश्यकताओं पर केंद्रित है, जो इसे DFI पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण 'नया जुड़ाव' बनाती है।

78-

Answer- (b)

Explanation- Statement 1 is incorrect. While NHB is the apex DFI for the housing sector, it is **no longer** a fully-owned subsidiary of the RBI. The RBI's stake in NHB was transferred to the Government of India in 2019, making it a fully government-owned institution. Statement 2 is correct. Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) was set up primarily to provide refinance support to banks, MFIs, and NBFCs for lending to micro-enterprises in the Shishu, Kishor, and Tarun categories. This refinancing mechanism is its core function. Statement 3 is correct. The Export-Import Bank of India (Exim Bank) is the principal financial institution for coordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services. Its specific mandate under the Exim Bank Act is restricted to financing and facilitating **foreign trade**. Thus, only statements 2 and 3 are correct.

व्याख्या- कथन 1 गलत है। हालाँकि NHB आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष DFI है, लेकिन यह अब RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **नहीं है**। NHB में RBI की हिस्सेदारी 2019 में भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी, जिससे यह पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व वाला संस्थान बन गया। कथन 2 सही है। सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी (MUDRA) को मुख्य रूप से शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए बैंकों, MFIs और NBFCs को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पुनर्वित्त तंत्र इसका मुख्य कार्य है। कथन 3 सही है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (Exim Bank) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कामकाज के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। Exim बैंक अधिनियम के तहत इसका विशिष्ट जनादेश केवल **विदेशी व्यापार** के वित्तपोषण और सुविधा तक ही सीमित है। इस प्रकार, केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

79-

Answer- (c)

Explanation- Statement 1 is correct. The Tendulkar Committee (2009) recommended poverty lines for 2011-12 prices as ₹816 (rural) and ₹1,000 (urban). The Rangarajan Committee (2014) recommended higher lines for the same year as ₹972 (rural) and ₹1,407 (urban). A higher poverty line automatically leads to a higher estimated Headcount Ratio (29.5% for Rangarajan vs. 21.9%

VAID IAS UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

for Tendulkar), reflecting the inclusion of more items (like nutritional, educational, and health components) in the basket compared to Tendulkar's methodology, which was criticized for low consumption norms. The Rangarajan methodology, focusing on a more robust 'minimum required consumption expenditure', inherently produced higher threshold values.**Statement 2 is correct.** The Current consumption-based poverty line, integrated with NSSO 2023-24 PLFS data, has the rural poverty line at ₹1,650 and the urban poverty line at ₹1,980 (at 2024 prices). This is consistent with the established trend where urban areas typically have a higher consumption threshold due to higher costs of living, including expenses on housing, transport, and non-subsidized services, which are accounted for in the consumption basket used for poverty estimation. Both statements are accurate as per the provided data.

व्याख्या- कथन 1 सही है। तेंदुलकर समिति (2009) ने 2011-12 की कीमतों पर ग्रामीण के लिए ₹816 और शहरी के लिए ₹1,000 की गरीबी रेखा की सिफारिश की थी। रंगराजन समिति (2014) ने उसी वर्ष के लिए उच्च सीमाएँ, ग्रामीण के लिए ₹972 और शहरी के लिए ₹1,407, की सिफारिश की। एक उच्च गरीबी रेखा स्वाभाविक रूप से उच्च अनुमानित हेडकाउंट अनुपात (तेंदुलकर के लिए 21.9% के मुकाबले रंगराजन के लिए 29.5%) की ओर ले जाती है, जो तेंदुलकर की पद्धति की तुलना में टोकरी में अधिक वस्तुओं (जैसे पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य घटक) को शामिल करने को दर्शाता है, जिसकी कम उपभोग मानदंडों के लिए आलोचना की गई थी। 'न्यूनतम आवश्यक उपभोग व्यय' पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाली रंगराजन कार्यप्रणाली ने स्वाभाविक रूप से उच्च सीमा मान दिए। **कथन 2 सही है।** वर्तमान उपभोग-आधारित गरीबी रेखा, जिसे NSSO 2023-24 PLFS डेटा के साथ एकीकृत किया गया है, ग्रामीण गरीबी रेखा को ₹1,650 और शहरी गरीबी रेखा को ₹1,980 (2024 की कीमतों पर) निर्धारित करती है। यह स्थापित प्रवृत्ति के अनुरूप है कि शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर रहने की लागत अधिक होने के कारण उपभोग की सीमा अधिक होती है, जिसमें आवास, परिवहन और गैर-सब्सिडी वाली सेवाओं पर व्यय शामिल है, जिसे गरीबी के अनुमान के लिए उपयोग की जाने वाली उपभोग टोकरी में शामिल किया जाता है। दिए गए डेटा के अनुसार दोनों कथन सही हैं।

80-

Answer- (d)

Explanation- The Marginal Cost of Funds based Lending Rate (**MCLR**) is primarily a mechanism introduced by the **Reserve Bank of India (RBI)** to improve the way changes in its policy rates (like the Repo Rate) are passed on to the actual loan interest rates offered by banks. While controlling inflation is a key function of the RBI through monetary policy tools, **MCLR itself is a framework for interest rate fixation** by commercial banks. Its direct objectives focus on making the lending rate transparent, fair, and responsive to policy rate changes, not on enabling the RBI to achieve its inflation targets, which is accomplished via the policy rates themselves.

Option **(a) To improve the transmission of policy rates into the lending rates of banks:** This is the **primary objective** of MCLR. It replaced the Base Rate system because transmission of policy rate cuts was slow under the previous regime.

Option **(b) To ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to borrowers as well as banks:** By linking lending rates to the **marginal cost of funds**, MCLR ensures that the rates

VAID ICS UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

reflect the current cost of raising funds for the bank, thus being fairer and more transparent to both parties.

Option **(c) To enable banks to become more competitive:** With MCLR, banks' lending rates are directly influenced by their own funding costs, encouraging them to manage costs efficiently and offer more competitive rates.

व्याख्या- मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (**MCLR**) मुख्य रूप से **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** द्वारा शुरू किया गया एक तंत्र है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी नीतिगत दरों (जैसे रेपो दर) में बदलाव बैंकों द्वारा दी जाने वाली वास्तविक ऋण ब्याज दरों तक बेहतर तरीके से पहुँचे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना मौद्रिक नीति उपकरणों के माध्यम से RBI का एक प्रमुख कार्य है, लेकिन **MCLR स्वयं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर निर्धारण के लिए एक ढाँचा है**। इसका सीधा उद्देश्य उधार दर को पारदर्शी, उचित और नीति दर में बदलाव के प्रति उत्तरदायी बनाना है, न कि RBI को उसके मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जो नीतिगत दरों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

विकल्प (a) नीतिगत दरों का बैंकों की उधार दरों में संचरण बेहतर बनाना: यह एमसीएलआर का प्राथमिक उद्देश्य है। इसने आधार दर प्रणाली का स्थान लिया क्योंकि पिछली व्यवस्था में नीतिगत दरों में कटौती का संचरण धीमा था।

विकल्प (b) उधारकर्ताओं और बैंकों दोनों के लिए उचित ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना: ऋण दरों को निधियों की सीमांत लागत से जोड़कर, एमसीएलआर यह सुनिश्चित करता है कि दरें बैंक के लिए धन जुटाने की वर्तमान लागत को प्रतिबिंबित करें, इस प्रकार यह दोनों पक्षों के लिए अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

विकल्प (c) बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम बनाना: एमसीएलआर के साथ, बैंकों की ऋण दरें सीधे उनकी स्वयं की वित्तपोषण लागतों से प्रभावित होती हैं, जिससे उन्हें लागतों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और अधिक प्रतिस्पर्धी दरें प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

81-

Answer- (a)

Explanation- Statement 1 is correct. India's three-stage nuclear power programme is designed to utilise its vast thorium reserves. The third stage specifically involves the use of **Thorium in Advanced Heavy Water Reactors (AHWRs)**, enabling a sustainable supply of nuclear fuel for large-scale electricity generation and marking the culmination of the self-reliance plan. **Statement 2 is incorrect** because, while the mission aims for long-term energy security and self-reliance, the target for **complete energy independence from uranium imports** has historically been associated with the 2050s or an unspecified long-term future, not rigidly 2047. Moreover, the mission's current, realistic goal is to expand nuclear capacity significantly to **22,480 MWe by 2031** and ensure long-term sustainability through the Fast Breeder Reactor (FBR) and AHWR technologies, not immediate, complete independence by a specific short-term date like 2047. The mission's focus is on building capacity and closing the fuel cycle, not a rigid, near-term import cessation goal.

व्याख्या- कथन 1 सही है। भारत का तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपने विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तीसरा चरण विशेष रूप से **उन्नत भारी जल रिएक्टरों (AHWRs) में थोरियम के उपयोग** से संबंधित है, जो बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ईंधन की एक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और आत्मनिर्भरता योजना की परिणति को चिह्नित करेगा। **कथन 2 गलत है** क्योंकि, हालाँकि मिशन का लक्ष्य दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और

VAID ICS:UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, लेकिन **यूरेनियम आयात से पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता** का लक्ष्य ऐतिहासिक रूप से 2050 के दशक या एक अनिर्दिष्ट दीर्घकालिक भविष्य से जुड़ा रहा है, न कि कठोर रूप से 2047 से। इसके अलावा, मिशन का वर्तमान, यथार्थवादी लक्ष्य **2031 तक परमाणु क्षमता को 22,480 मेगावाट** तक बढ़ाना और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) तथा AHWR प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है, न कि 2047 जैसी किसी विशिष्ट अल्पकालिक तिथि तक तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। मिशन का ध्यान क्षमता निर्माण और ईंधन चक्र को बंद करने पर है।

82-

Answer- (b)

Explanation- The statement (b) is correct. The **6X6X6 strategy** is a strategic framework adopted by the **World Health Organization (WHO)** for combating **Malaria**. Specifically, it was designed in the context of the **Greater Mekong Subregion (GMS)**, which includes six countries: Cambodia, China (Yunnan Province), Lao People's Democratic Republic, Myanmar, Thailand, and Vietnam. The strategy is built around six key technical components, such as prompt diagnosis, appropriate treatment, and surveillance, intended to accelerate malaria elimination efforts across these six countries over a six-year period, with the overarching goal of eliminating all forms of malaria in the GMS by 2030. The emphasis of the strategy is particularly on combating **artemisinin resistance** which poses a significant threat to global malaria control efforts, necessitating a coordinated regional approach for its elimination.

व्याख्या- कथन (b) सही है। 6X6X6 रणनीति एक रणनीतिक ढाँचा है जिसे **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा **मलेरिया** से लड़ने के लिए अपनाया गया था। विशेष रूप से, इसे **ग्रेटर मेकांग उपक्षेत्र (GMS)** के संदर्भ में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें छह देश शामिल हैं: कंबोडिया, चीन (युन्नान प्रांत), लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। यह रणनीति छह मुख्य तकनीकी घटकों, जैसे त्वरित निदान, उचित उपचार और निगरानी के आसपास निर्मित है, जिसका उद्देश्य इन छह देशों में मलेरिया उन्मूलन प्रयासों को छह साल की अवधि में तेज करना है, जिसका व्यापक लक्ष्य 2030 तक GMS में मलेरिया के सभी रूपों को समाप्त करना है। इस रणनीति का जोर विशेष रूप से **आर्टेमिसिनिन प्रतिरोध** से लड़ने पर है, जो वैश्विक मलेरिया नियंत्रण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, जिससे इसके उन्मूलन के लिए एक समन्वित क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक हो गया है।

83-

Answer- (b)

Explanation- The correct answer is (b) Cape Town Convention, 2001. The Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025, is specifically aimed at implementing the **Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment (2001)** and its related **Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment**. India ratified the Convention in 2008, but the new legislation provides the domestic legal framework necessary for its effective implementation, particularly concerning the rights of lessors and financiers to repossess aircraft during an airline's insolvency. This move is expected to significantly reduce aircraft leasing costs for Indian carriers by providing a globally-compliant, predictable legal environment.

VAID IAS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

व्याख्या- सही उत्तर (b) केप टाउन कन्वेंशन, 2001 है। विमान वस्तु में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025, विशेष रूप से **मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर केप टाउन कन्वेंशन (2001)** और इसके संबंधित **विमान उपकरण विशिष्ट प्रोटोकॉल** को लागू करने के उद्देश्य से लाया गया है। भारत ने 2008 में कन्वेंशन की पुष्टि की थी, लेकिन नया कानून इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक घरेलू कानूनी ढांचा प्रदान करता है, विशेष रूप से एक एयरलाइन के दिवालियापन के दौरान पट्टेदारों और फाइनेंसरों के विमान पर कब्ज़ा करने के अधिकारों से संबंधित है। इस कदम से वैश्विक स्तर पर अनुपालन योग्य और अनुमानित कानूनी माहौल प्रदान करके भारतीय वाहकों के लिए विमान लीजिंग लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है।

84-

Answer- (c)

Explanation- Mitathal and Tighrana are significant archaeological sites located in the Bhiwani district of **Haryana**. They have long been recognized as important settlements of the **Indus Valley Civilization** (Harappan period). Recently, the sites made news because the **Haryana State Government** officially declared them as **protected archaeological monuments** under the state's archaeological laws. This declaration ensures their preservation and safeguards them from encroachment and damage, recognizing their historical importance for studying the different phases of the Harappan culture in the region.

व्याख्या- मिताथल और तिघराना हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित महत्वपूर्ण **पुरातात्विक स्थल** हैं। इन्हें लंबे समय से **सिंधु घाटी सभ्यता** (हड़प्पा काल) की महत्वपूर्ण बस्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

हाल ही में, ये स्थल तब खबरों में आए जब **हरियाणा राज्य सरकार** ने राज्य के पुरातात्विक कानूनों के तहत आधिकारिक तौर पर इन्हें **संरक्षित पुरातात्विक स्मारक** घोषित कर दिया। यह घोषणा सुनिश्चित करती है कि क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न चरणों के अध्ययन के लिए उनके ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए, उन्हें अतिक्रमण और क्षति से बचाया और संरक्षित किया जा सके।

85-

Answer- (b)

Explanation- The **Fiscal Deficit to GSDP Ratio** is the most fundamental indicator used in the Fiscal Health Index (FHI) to assess a state's financial stability. Fiscal Deficit represents the total borrowing requirement of the state, and comparing it to the **Gross State Domestic Product (GSDP)**, which is the size of the state's economy, reveals the relative burden of debt. A lower ratio indicates greater fiscal discipline and a lower risk to the state's financial future. Options (a), (c), and (d) are macroeconomic or national-level indicators and are not typically used to directly measure a state's budgetary performance.

व्याख्या- राजकोषीय घाटा से GSDP अनुपात (Fiscal Deficit to GSDP Ratio) किसी राज्य की वित्तीय स्थिरता का आकलन करने के लिए फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) में उपयोग किया जाने वाला सबसे मौलिक संकेतक है। राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधार आवश्यकता को दर्शाता है, और इसे **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)**, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार है, से तुलना करने पर ऋण के सापेक्ष बोझ का पता चलता है। कम अनुपात अधिक राजकोषीय अनुशासन और राज्य के वित्तीय भविष्य के लिए कम जोखिम को इंगित करता है। विकल्प (a), (c), और (d) व्यापक आर्थिक या राष्ट्रीय स्तर के संकेतक हैं और इनका उपयोग सीधे राज्य के बजटीय प्रदर्शन को मापने के लिए नहीं किया जाता है।

VAID PCS/UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

86-

Answer- (c)

Explanation- The Fram2 mission, launched by SpaceX is a private crewed flight to polar orbit featuring 22 experiments on human health and space sustainability. Among these, the **"Mission MushVroom"** experiment aims to grow **oyster mushrooms** in microgravity for the first time, providing data on fungi as a nutrient-dense, efficient crop for long-duration missions like those to Mars. This supports sustainable food systems in space, where traditional agriculture is challenging. Option (a) is incorrect, as reproductive health studies focus on short-term hormone effects, not long-term. Option (b) is wrong; the mission's innovation is the first in-space X-ray, not ultrasound. Option (d) is false; the duration was 3.5 days, insufficient for notable bone density changes.

व्याख्या- स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया Fram2 मिशन, एक निजी मानवयुक्त उड़ान है जो ध्रुवीय कक्षा (polar orbit) में है और इसमें मानव स्वास्थ्य तथा अंतरिक्ष स्थिरता पर 22 प्रयोग शामिल हैं। इनमें से, "मिशन मशरूम" ('Mission MushVroom') प्रयोग का लक्ष्य पहली बार सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (microgravity) में सीप मशरूम (oyster mushrooms) उगाना है, जो मंगल जैसे लंबे मिशनों के लिए कवक (fungi) को एक पोषक तत्वों से भरपूर, कुशल फसल के रूप में डेटा प्रदान करेगा। यह अंतरिक्ष में टिकाऊ खाद्य प्रणालियों का समर्थन करता है, जहाँ पारंपरिक कृषि चुनौतीपूर्ण है। विकल्प (a) गलत है, क्योंकि प्रजनन स्वास्थ्य अध्ययन दीर्घकालिक के बजाय अल्पकालिक हार्मोन प्रभावों पर केंद्रित हैं। विकल्प (b) गलत है; मिशन का नवाचार पहली बार अंतरिक्ष में एक्स-रे है, अल्ट्रासाउंड नहीं। विकल्प (d) असत्य है; इसकी अवधि 3.5 दिन थी, जो उल्लेखनीय अस्थि घनत्व परिवर्तनों के लिए अपर्याप्त है।

87-

Answer- (d)

Explanation- Statement 1 is incorrect: The Ottawa Convention, also known as the Anti-Personnel Mine Ban Treaty, is a **binding** international agreement, not a non-binding one. Its core purpose is to prohibit the use, stockpiling, production, and transfer of anti-personnel landmines.

Statement 2 is incorrect: The treaty specifically prohibits **anti-personnel** landmines. The text explicitly states that **anti-vehicle mines are not banned** by the Convention. The Convention's scope is strictly limited to anti-personnel mines and includes provisions for assisting their victims. Since both statements contain factual inaccuracies regarding the nature and scope of the treaty, the correct option is (d).

व्याख्या- कथन 1 गलत है: ओटावा कन्वेंशन एक **बाध्यकारी** अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, न कि गैर-बाध्यकारी। इसका उद्देश्य एंटी-पर्सनल लैंडमाइन्स (बारूदी सुरंगों) के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण पर रोक लगाना है। यह इसकी कानूनी स्थिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

कथन 2 गलत है: यह संधि केवल एंटी-पर्सनल लैंडमाइन्स को प्रतिबंधित करती है। प्रदान की गई जानकारी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **एंटी-व्हीकल माइन्स** (वाहन-रोधी खदानें) संधि द्वारा **प्रतिबंधित नहीं** हैं।

88-

Answer- (c)

VAID IAS|UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

Explanation- The **PM E-DRIVE** (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) Scheme is overseen by the **Ministry of Heavy Industries (MHI)**. This ministry is the nodal authority for promoting the domestic manufacturing and adoption of automobiles and auto components, including electric vehicles.

व्याख्या- पीएम ई-ड्राइव (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना **भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries - MHI)** के तत्वावधान में शुरू की गई है। यह मंत्रालय ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, के घरेलू विनिर्माण और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए नोडल प्राधिकरण है।

89-

Answer- (b)

Explanation- The Panchayat Advancement Index (PAI) is designed as a multi-domain and multi-sectoral tool to measure the holistic development of Panchayats towards achieving Localized Sustainable Development Goals (LSDGs), particularly **LSDG-1: No Poverty**. For an index aiming at *advancement* and evidence-based policymaking, measuring poverty effectively requires a **multi-dimensional approach**. Relying solely on scheme registration (a), an absolute count (c), or fund disbursement (d) provides only a partial picture. Option (b), **a combination of income proxies, ownership of essential assets (e.g., housing, vehicles), and access to basic necessities (e.g., electricity, clean cooking fuel)**, is the most comprehensive method. This approach aligns with the global Multi-dimensional Poverty Index (MPI) framework, accurately capturing various forms of deprivation and providing granular data essential for identifying specific developmental gaps at the grassroots level.

व्याख्या- पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) को स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs), विशेष रूप से **LSDG-1: गरीबी नहीं**, को प्राप्त करने की दिशा में पंचायतों के समग्र विकास को मापने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय उपकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया है। *उन्नति* और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण पर केंद्रित सूचकांक के लिए, गरीबी को प्रभावी ढंग से मापने हेतु **बहु-आयामी दृष्टिकोण** की आवश्यकता होती है। केवल योजना पंजीकरण (a), एक पूर्ण संख्या (c), या निधि संवितरण (d) पर निर्भर रहना केवल आंशिक जानकारी देता है। विकल्प (b), **आय के प्रॉक्सी (जैसे उपभोग), आवश्यक संपत्ति के स्वामित्व और खाना पकाने के ईंधन और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का संयोजन**, सबसे व्यापक तरीका है। यह दृष्टिकोण वैश्विक बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI) ढाँचे के साथ संरेखित होता है, जो अभावों के विभिन्न रूपों को सटीक रूप से दर्शाता है और जमीनी स्तर पर विशिष्ट विकासात्मक अंतराल की पहचान करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म डेटा प्रदान करता है।

90-

Answer- (c)

Explanation- The primary implication of **high household indebtedness** on macroeconomic stability is that **it increases the sensitivity** of indebted households to adverse financial shocks. When inflation rises, the real burden of debt repayment is not reduced significantly, while the

VAID ICS UPSC (CSE) PRE-2026 MOCK TEST SERIES

cost of living increases. Similarly, when interest rates rise, the direct cost of servicing floating-rate loans increases. Faced with these higher costs, indebted households must **sharply cut spending** to meet debt obligations. This simultaneous reduction in consumption spending by a large segment of the population during an economic downturn **amplifies macroeconomic volatility**, making the economy more susceptible to deep and prolonged crises.

व्याख्या- उच्च घरेलू ऋणग्रस्तता का समष्टि आर्थिक स्थिरता पर प्राथमिक निहितार्थ यह है कि यह ऋणग्रस्त परिवारों की प्रतिकूल वित्तीय झटकों के प्रति **संवेदनशीलता को बढ़ाता है**। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो ऋण चुकाने का वास्तविक बोझ अधिक हो जाता है, जबकि जीवन-यापन की लागत भी बढ़ जाती है। इसी तरह, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो फ्लोटिंग-दर वाले ऋणों की सर्विसिंग की प्रत्यक्ष लागत बढ़ जाती है। इन उच्च लागतों का सामना करने पर, ऋणग्रस्त घरों को ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए **खर्च में तेज़ी से कटौती** करनी पड़ती है। आर्थिक मंदी के दौरान आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा उपभोग व्यय में यह एक साथ कमी **समष्टि आर्थिक अस्थिरता को बढ़ाती है**, जिससे अर्थव्यवस्था गहरे और लंबे संकटों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।

91-

Answer- (b)

Explanation- The Bridge Inventory and Condition Rating System (**BICRS**) is a **mandatory** system launched by the **National Highways Authority of India (NHAI)**. Its primary purpose is to ensure **comprehensive bridge health assessment and inventory management** for bridges under NHAI's jurisdiction, which includes National Highways. This digitized system helps in systematically collecting and maintaining data on all assets, classifying their condition, and prioritizing rehabilitation/repair work based on a condition rating scale. This crucial initiative ensures the structural safety and serviceability of bridges across the network, moving bridge maintenance from a reactive to a **proactive and data-driven approach**. The mandatory nature under NHAI makes option (b) the accurate description.

व्याख्या- यह प्रणाली **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)** द्वारा शुरू की गई एक **अनिवार्य** प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य NHAI के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलों के लिए **व्यापक पुल स्वास्थ्य मूल्यांकन और इन्वेंट्री प्रबंधन** सुनिश्चित करना है। यह डिजिटल प्रणाली सभी संपत्तियों पर डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने और बनाए रखने, उनकी स्थिति को वर्गीकृत करने और एक कंडीशन रेटिंग स्केल के आधार पर मरम्मत कार्य को प्राथमिकता देने में मदद करती है। यह महत्वपूर्ण पहल पूरे नेटवर्क में पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे पुल रखरखाव एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से हटकर **सक्रिय और डेटा-संचालित दृष्टिकोण** की ओर बढ़ता है। NHAI के तहत इसकी अनिवार्य प्रकृति विकल्प (b) को सटीक बनाती है।

92-

Answer- (a)

Explanation- The **Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA)** is a globally significant framework for advancing women's rights and gender equality. It was unanimously adopted at the **Fourth World Conference on Women** held in **Beijing, China, in 1995**. The BPfA is a

VAID ICS:UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

comprehensive global policy agenda that identifies 12 critical areas of concern, ranging from poverty and health to education, violence against women, and women in power and decision-making. It established concrete commitments and actions for governments, international organizations, and civil society to implement. It remains the most progressive blueprint ever for advancing women's rights, and its anniversary reviews (e.g., Beijing +25) are crucial moments for assessing global progress. The document marked a turning point in the global commitment to gender equality, recognizing that women's empowerment is a prerequisite for achieving sustainable development and poverty eradication. Its continued relevance is underscored by its use as a benchmark for measuring progress on Sustainable Development Goal 5 (Gender Equality).

व्याख्या- बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच (BPfA) महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण ढाँचा है। इसे **1995 में बीजिंग, चीन** में आयोजित **चौथा विश्व महिला सम्मेलन** में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। BPfA एक व्यापक वैश्विक नीति एजेंडा है जो गरीबी और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, और सत्ता और निर्णय लेने में महिलाओं तक, 12 महत्वपूर्ण चिंता के क्षेत्रों की पहचान करता है। इसने सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के लिए लागू करने हेतु ठोस प्रतिबद्धताएँ और कार्य स्थापित किए। यह महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अब तक की सबसे प्रगतिशील रूपरेखा बनी हुई है, और इसकी वर्षगाँठ समीक्षाएँ (जैसे, बीजिंग +25) वैश्विक प्रगति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण क्षण हैं। इस दस्तावेज़ ने लैंगिक समानता के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया, यह मानते हुए कि महिलाओं का सशक्तिकरण सतत विकास और गरीबी उन्मूलन प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त है। सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) पर प्रगति को मापने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में इसके उपयोग से इसकी निरंतर प्रासंगिकता रेखांकित होती है।

93-

Answer- (c)

Explanation- Statement **(c)** is incorrect because the primary function of the **Cu-Phen** nanozyme is to mimic **peroxidase** (Option b is correct). It catalyzes the production of **Reactive Oxygen Species (ROS)**, such as hydroxyl radicals (OH), from hydrogen peroxide (H_2O_2). These ROS are **toxic** and are the key agents used for the nanozyme's **antimicrobial activity** against pathogens. Therefore, it deliberately produces harmful reactive oxygen species, directly contradicting the claim in statement (c). Options (a) and (d) correctly describe its development by **CSIR-CLRI** and the validation techniques used.

व्याख्या- कथन **(c)** गलत है क्योंकि **Cu-Phen** नैनोज़ाइम का मुख्य कार्य **परऑक्सीडेज़** (विकल्प b सही है) की नकल करना है। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड (H_2O_2) से **प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (ROS)**, जैसे हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स (OH) के उत्पादन को उत्प्रेरित करता है। ये ROS **हानिकारक** होते हैं और नैनोज़ाइम की **रोगाणुरोधी गतिविधि** के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कारक हैं। इसलिए, यह जानबूझकर हानिकारक ROS उत्पन्न करता है, जो कथन (c) में किए गए दावे के सीधे विपरीत है। विकल्प (a) और (d) **CSIR-CLRI** द्वारा इसके विकास और उपयोग की गई सत्यापन तकनीकों का सही वर्णन करते हैं।

94-

VAID ICS UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

Answer- (c)

Explanation- Statement 1 is correct. The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 explicitly provides the legal foundation for the CCTS by granting the Central Government the authority to establish a carbon market.

Statement 2 is also correct. The initial implementation of the CCTS is focused on sectors like Aluminium, Cement, and Power because they are the primary emitters of greenhouse gases in India.

व्याख्या- कथन 1 सही है। ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 केंद्र सरकार को कार्बन बाज़ार स्थापित करने का अधिकार देकर CCTS के लिए स्पष्ट रूप से कानूनी आधार प्रदान करता है।

कथन 2 भी सही है। CCTS का प्रारंभिक कार्यान्वयन एल्युमीनियम, सीमेंट और बिजली जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है क्योंकि ये भारत में ग्रीनहाउस गैसों के प्राथमिक उत्सर्जक हैं।।

95-

Answer- (b)

Explanation- The correct statement is (b). The India Justice Report 2025, a collaborative effort by Tata Trusts and civil society organizations like DAKSH and Vidhi Centre, evaluates states' justice delivery capacity across four pillars—police, prisons, judiciary, and legal aid. It relies solely on government data to rank states on metrics including human resources, budgets, infrastructure, workload, and diversity, highlighting gaps like judicial vacancies and prison overcrowding. This data-driven approach promotes reforms for accessible justice, unlike the narrow focuses in other options.

व्याख्या- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, **टाटा ट्रस्ट्स** और **DAKSH** तथा **विधि सेंटर** जैसे सिविल सोसाइटी संगठनों का एक सहयोगी प्रयास है, जो चार स्तंभों—**पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता**—में राज्यों की न्याय वितरण क्षमता का मूल्यांकन करती है। यह मानव संसाधन, बजट, बुनियादी ढाँचा, कार्यभार और विविधता सहित विभिन्न मापदंडों पर राज्यों को रैंक करने के लिए **केवल सरकारी डेटा** पर निर्भर करती है, और न्यायिक रिक्तियों तथा जेलों में भीड़भाड़ जैसी कमियों को उजागर करती है। यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण सुलभ न्याय के लिए सुधारों को बढ़ावा देता है, जो अन्य विकल्पों के संकीर्ण फोकस से अलग है।

96-

Answer- (a)

Explanation- Statement **1 is correct**: India became a **State Party** to the UNESCO World Heritage Convention after ratifying it in **1977**. Statement **2 is incorrect**: Nominations are channelled through the **Ministry of Culture**, after being placed on the **Tentative List**, not directly by the ASI to the Committee. Statement **3 is incorrect**: India does have a **Mixed Site** on the World Heritage List—**Khangchendzonga National Park** in Sikkim—which is recognized for both its outstanding natural features and its cultural significance.

व्याख्या- कथन **1 सही है**: भारत ने 1977 में इसकी पुष्टि करने के बाद यूनेस्को विश्व धरोहर अभिसमय **का पक्षकार राष्ट्र** बन गया। कथन **2 गलत है**: नामांकन **संस्कृति मंत्रालय** के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिन्हें **अस्थायी सूची (Tentative List)** में रखा

VAID IAS:UPSC (CSE) PRE 2026: MOCK TEST SERIES

जाता है, न कि ASI द्वारा सीधे समिति को। कथन **3 गलत है**: भारत के पास विश्व धरोहर सूची में **एक मिश्रित स्थल** है—सिक्किम में **खांगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान**—जिसे इसकी उत्कृष्ट प्राकृतिक विशेषताओं और सांस्कृतिक महत्व दोनों के लिए मान्यता प्राप्त है।

97-

Answer- (b)

Explanation- Statement **(b)** best describes the primary focus. UNESCO's **Memory of the World Programme (MoW)** was established in 1992 to prevent the irreversible loss of **documentary heritage**—the world's collective memory. This heritage includes valuable records in various formats such as **manuscripts, books, films, sound recordings, photographs, and oral traditions**. The MoW Register identifies and lists this documentary heritage of global significance and promotes its preservation and universal accessibility. Options (a) and (c) relate to the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions, respectively.

व्याख्या- कथन **(b)** प्राथमिक फोकस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यूनेस्को का **मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम (MoW)** दुनिया की सामूहिक स्मृति—**दस्तावेज़ी विरासत** के अपरिवर्तनीय नुकसान को रोकने के लिए 1992 में स्थापित किया गया था। इस विरासत में विभिन्न स्वरूपों में मूल्यवान रिकॉर्ड शामिल हैं, जैसे **पांडुलिपियाँ, किताबें, फिल्में, ध्वनि रिकॉर्डिंग, तस्वीरें और मौखिक परंपराएँ**। MoW रजिस्टर वैश्विक महत्व की इस दस्तावेज़ी विरासत की पहचान करता है और उसे सूचीबद्ध करता है, तथा इसके संरक्षण और सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देता है। विकल्प (a) और (c) क्रमशः विश्व विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अभिसमयों से संबंधित हैं।

98-

Answer- (b)

Explanation- The **Grand Challenges** initiative is primarily launched and supported by the **Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)**. Started in 2003, this initiative fosters **innovation** to solve key health and development problems, especially in low- and middle-income countries. It uses an **open-call process** to solicit bold, unconventional ideas from researchers globally, offering **seed grants** to test early-stage concepts that could lead to breakthroughs in areas like maternal health, disease control, and agricultural development. The BMGF drives the core strategy and funding for the network.

व्याख्या- ग्रैंड चैलेंजेज पहल मुख्य रूप से **बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF)** द्वारा शुरू और समर्थित है। 2003 में शुरू की गई, यह पहल विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रमुख स्वास्थ्य और विकास समस्याओं को हल करने के लिए **नवाचार** को बढ़ावा देती है। यह मातृ स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण और कृषि विकास जैसे क्षेत्रों में सफलताओं की ओर ले जाने वाली प्रारंभिक चरण की अवधारणाओं का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ताओं से साहसी, अपरंपरागत विचारों को आमंत्रित करने के लिए एक **खुला-कॉल प्रक्रिया** का उपयोग करती है, जिसमें **सीड ग्रांट** (प्रारंभिक अनुदान) दिए जाते हैं। BMGF इस नेटवर्क की मुख्य रणनीति और फंडिंग को संचालित करता है।

99-

Answer- (c)

VAID ICS: UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES

Explanation- The **SAARC Visa Exemption Scheme (SVES)** does **not** grant visa-free travel to all citizens or general tourists. It is a limited scheme designed to facilitate official travel for **High-ranking officials, Supreme Court Justices/Judges, Parliamentarians, certain categories of journalists, business professionals, and other designated dignitaries** from SAARC Member States. The goal is to promote closer regional cooperation and official contact by easing travel restrictions for persons holding specific positions of responsibility who are contributing to the regional cooperation agenda.

व्याख्या- सार्क वीज़ा छूट योजना (SVES) सभी नागरिकों या सामान्य पर्यटकों को वीज़ा-मुक्त यात्रा की अनुमति **नहीं** देती है। यह एक सीमित योजना है जिसे सार्क सदस्य देशों के **उच्च पदस्थ अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसदों, कुछ श्रेणियों के पत्रकारों, व्यावसायिक पेशेवरों, और अन्य नामित गणमान्य व्यक्तियों** के लिए आधिकारिक यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग एजेंडे में योगदान देने वाले विशिष्ट पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील देकर घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग और आधिकारिक संपर्क को बढ़ावा देना है।

100-

Answer- (a)

Explanation- The Periyar Tiger Reserve in Kerala is a **terrestrial** protected area, renowned for its tiger and elephant population and located inland around a lake and river system. It is **not** a Marine Protected Area (MPA). MPAs are designated areas in the ocean or coastal regions where activities are regulated. Options (b) **Bhitarkanika**, (c) **Malvan Marine**, and (d) **Coringa** are all coastal or estuarine protected areas in India, recognized as MPAs or having significant marine/coastal components protected under wildlife laws.

व्याख्या- केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व एक **स्थलीय** संरक्षित क्षेत्र है, जो अपने बाघों और हाथियों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है और एक झील तथा नदी प्रणाली के आसपास अंतर्देशीय (inland) स्थित है। यह एक **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) नहीं** है। MPA वे क्षेत्र हैं जो समुद्र या तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ मानवीय गतिविधियाँ विनियमित होती हैं। विकल्प (b) **भीतरकनिका**, (c) **मालवन मरीन**, और (d) **कोरिंगा** सभी भारत में तटीय या मुहाना (estuarine) संरक्षित क्षेत्र हैं, जिन्हें MPA के रूप में मान्यता प्राप्त है या वन्यजीव कानूनों के तहत संरक्षित महत्वपूर्ण समुद्री/तटीय घटक हैं।

****

VAID ICS:UPSC (CSE) PRE-2026: MOCK TEST SERIES